वर्ष-10//अंक-1//अक्टूबर 2021
ISSN 2454–5805
₹20/-
RNI NO.: CHHHIN/2013/50684

आम आदमी पत्रिका®

एक आम इंसान की सोच

छत्तीसगढ़ बनेगा देश का मिलेट हब

» 6

मक्का से बनेगा इथेनाल

» 8

गोबर से बढ़ने लगी आय

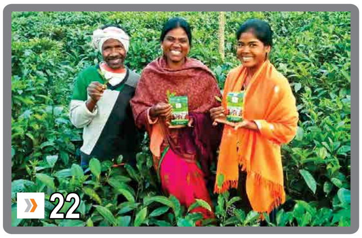

» 22

विकास का छत्तीसगढ़ मॉडल

www.aamaadmi.in
www.aamaadmee.com

बेहतर प्राकृतिक जीवन के लिए...

अपनाएं 100% शुद्ध ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स

ORGALIFE®

Eat Organic, Stay Healthy

माउथ फ्रेशनर | पिंक रॉक सॉल्ट | गुड़ | चाय मसाला

MARKETED By : **ORGALIFE FOOD & BEVERAGES (INDIA)**

For Trade Queries/Suggestions +91-9755166633 care@orgalife.in Follow us on

आम आदमी पत्रिका

वर्ष-10//अंक-1//अक्टूबर 2021

प्रबंध संपादक	:	उमेश के बंसी
संपादक	:	प्रत्यूष शर्मा
विशेष संवाददाता	:	अनुपम सोनी (दिल्ली)
सर्कुलेशन इंचार्ज	:	प्रकाश बंसी
रिपोर्टर	:	नेहा श्रीवास्तव
कंटेंट राईटर	:	प्रशांत पारीक
विडियो एडिटर	:	शुभम शर्मा
क्रिएटिव डिजाइनर	:	देवेन्द्र देवांगन
मैग्ज़ीन डिज़ाइनर	:	युनिक ग्राफिक्स
एडमिनिस्ट्रेशन	:	दीपल राठोड़
अकाउंट असिस्टेंट	:	कुसुमलता बघेल
ऑफिस कॉर्डिनेटर	:	योगेन्द्र बिसेन

प्रधान कार्यालय

965/1 कक्कड़ चौक, श्याम नगर रोड,
कटोरा तालाब,रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन : 0771-4044047

ईल : khabar@aamaadmi.in

कार्यालय

प्लाट नं.118, कंचन बाग, राजनांदगांव

प्रकाशक

उमेश कुमार बंसी, क्वाटर नंबर 10, एम.एम. रियल स्टेट कॉलोनी, अमलीडीह, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित एवं मुद्रित

विशेष- इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिये गए विचार, लेखकों के अपने है। इसमें संपादक / मुद्रक की सहमति अनिवार्य नहीं है। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संपादक / मुद्रक जिम्मेदार नहीं होगा। इस पत्रिका से संबंधित किसी भी विवाद के लिए सुनवाई क्षेत्र रायपुर न्यायालय होगा।

अक्टूबर 2021

इस अंक में

वनों की गोद में बसे कोण्डागांव जिले में 90 प्रतिशत से अधिक आबादी वनांचलों में निवास करती है। वनों की सघनता एवं पर्वतीय स्थल संरचना के कारण यहां मैदानी क्षेत्रों की तरह खेती संभव नहीं हो पाती है। 8

जब सीएम भूपेश से महानायक बच्चन ने किया ये सवाल 12

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार...

नई औद्योगिक नीति से राज्य में बना नया औद्योगिक वातावरण 18

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा...

खाद की कमाई से खरीदी स्मार्ट फोन 21

धुरी धुरी के जीवन की धुरी पहले उसके घर एवं परिवार तक सीमित थी।

सोलर पंप बने फसलों के लिए संजीवनी 26

राज्य के कई इलाकों में अल्प वर्षा के चलते खरीफ फसलों को...

अब ममता की दिल्ली पर नजर 28

'भवानीपुर में ममता बनर्जी की जीत कोई मुद्दा नहीं थी।

एयर पॉल्यूशन से गर्भ में पल रहे बच्चे को खतरा 30

एयर पॉल्यूशन का असर गर्भवती महिलाओं ...

आखिर ये छत्तीसगढ़ में चल क्या रहा है।

उमेश के बंसी
(प्रबंध संपादक)

छत्तीसगढ़ की राजनीति में सीएम की कुर्सी को लेकर सवाल सबके मन में है और ये ढाई साल होने के पहले से चल है, पर क्या होने वाला है कब होने वाला है, कैसे होने वाला है। सबके मन में कौतुहल मचा हुआ है और हो भी क्यों न। राजनीति ही कुछ ऐसी चीज है। जिसमें स्थिरता तो रहती है, पर पार्टी के नेता ही मुखर हो जाएं, तब तो कुछ भी नहीं कहां जा सकता। एक समय ऐसा था कि प्रदेश के सत्ता पक्ष के 50 विधायक दिल्ली पहहुंच गए। वहां शक्ति प्रदर्शन किए थे, तब कुछ दिन के बाद वहां से लौटे और यहां जोशीला स्वागत सीएम का हुआ था, कुछ समय पूरा मामला शांत रहा, लेकिन अब फिर वहीं सिलसिला शुरू हो गया है। आपको याद हो कि जब असम में चुनाव हुए थे, तो सीएम भूपेश को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। हालाकिं जिम्मेदारी का निर्वहन भी अच्छे से किया, लेकिन कांग्रेस सत्ता में नहीं आई। पर उत्तर प्रदेश में कुछ इसी तरह की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में बात ये उठ रही है कि कुर्सी से उन्हें हाथ धोना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लगता। सबकुछ बेहतर चल रहा है, ऐसे में सीएम बदलने कि जरूरत भी पार्टी को नहीं होनी चाहिए। आलकमान मानता है कि बड़ी जिम्मेदारी के काम भूपेश बघेल ही कर सकते हैं। यह मानने की वजह यह है कि भूपेश बघेल कांग्रेस के ऐसे नेता है जो काम कोई कांग्रेस नेता नहीं कर सका, वह काम भूपेश बघेल ने कर दिखाया। यह काम था तीन विधानसभा चुनाव हार चुकी छत्तीसगढ़ कांग्रेस को विधानसभा चुनाव जिताना। वह भी बड़े बहुमत से। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत से भूपेश बघेल का कद बढ़ा। उन्हें छत्तीसगढ़ की सत्ता सौंपी गई। पिछले ढाई साल में भूपेश बघेल ने राज्य में एक भी चुनाव नहीं हारे हैं तथा कांग्रेस को राज्य में इतना मजबूत किया है कि कांग्रेस चुनाव जीतने के विषय में ही सोचती है तथा जीतती भी है। इसी जीतने वाली सोच के चलते कांग्रेस आलाकमान ने भूपश बघेल का असम चुनाव जीतने की जिम्मेदारी सौंपी थी। वहां पर कांग्रेस चुनाव नहीं जीत सकी, लेकिन चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। अब भूपेश बघेल को यूपी का विधानसभा चुनाव जिताने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह असम से बड़ी चुनौती है क्योंकि असम में कांग्रेस का भाजपा से आमने -सामने मुकाबला था। यूपी में बहुत सारे दलों के बीच कांग्रेस को जिताना है। सभी दल ऐसे हैं जो एक दूसरे का वोट ही काटेंगे। यहां सपा, बसपा, कांग्रेस, ओवेशी,केजरीवाल है तथा सभी भाजपा को हराकर सरकार बनाना चाहते हैं। इतने दलों के बीच कांग्रेस को जिताने का काम आासन नहीं है। यूपी में कांग्रेस इससे पहले राहुल गांधी के नेतृत्व चुनाव लड़ चुकी है लेकिन वह जीत नहीं सकी। इससे उसको नुकसान ही हुआ तथा सपा दूसरी नंबर की पार्टी बन गई। कांग्रेस वर्तमान में चौथे नंबर की पार्टी है। बसपा तीसरे नंबर की पार्टी है। राज्य में कांग्रेस को सपा व बसपा से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करना है। सपा व बसपा सत्ता में रह चुके हैं, जबकि कांग्रेस कई सालों से सत्ता से बाहर है। ऐसे में कांग्रेस को सपा व बसपा से ज्यादा भरोसे की पार्टी बनाना एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का बीड़ा भूपेशबघेल ने उठाया है तो वह उम्मीद की जा सकती है कि भूपेश बघेल ऐसा करने अपना पूरा जोर लगा देंगे। वह कांग्रेस को जिताने के लिए कोई कोरकसर नहीं छोड़ेगे। यूपी में कांग्रेस को मजबूत करने का काम प्रियंका गांधी कर रही हैं। इसलिए इसबार उनकी प्रतिष्ठा दांव पर रहेगी। भूपेश बघेल को उनकी प्रतिष्ठा बचानी है। यह तब ही होगा जब कांग्रेस यूपी में जितेगी या अच्छा प्रदर्शन करेगी।

नरवा उपचार से भू-जल स्तर बढ़ा सिंचित रकबा में भी बढोत्तरी

दोहरी फसल लेने लगे किसान

शासन की सुराजी गांव योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में नरवा विकास के बेहतर परिणाम दिखाई देने लगे हैं। जिन इलाकों में बरसाती नालों में वर्षा जल के संरक्षण के लिए स्थायी संरचनाएं निर्मित किए गए हैं। उन इलाकों के भू-जल स्तर में वृद्धि के साथ-साथ सिंचाई की सुविधा भी बढ़ी है। नाले में पानी उपलब्ध होने के कारण किसान इसका उपयोग सिंचाई के लिए करने के साथ-साथ अब नगदी और दोहरी फसल का उत्पादन भी करने लगे हैं। नरवा उपचार की वजह से भूमि का कटाव भी रूका है। हरियाली में वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में 60 नालों का उपचार कराए जाने की वजह से आसपास के गांवों के भू-जल स्तर में औसतन 5-10 सेंटीमीटर की वृद्धि होने के साथ ही लगभग 1240 हेक्टेयर रकबे में सिंचाई की वास्तविक सुविधा सृजित हुई है।

नरवा विकास कार्यक्रम से ग्रामीण क्षेत्रों में खेती-किसानी और किसानों की खुशहाली की नई राहें खुली है। बलरामपुर जिले में कुल 60 नालों के उपचार के लिए 6 हजार 828 कार्य कराए गए, जिसमें मुख्यतः डबरी निर्माण, बोल्डर चेक, गेबियन संरचना, कन्टुर ट्रेंच, कूप, मिट्टी बांध, चेकडेम, तालाब, स्टॉप डेम आदि का निर्माण शामिल हैं। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में निर्मित 343 डबरी से 768 हेक्टेयर, 09 चेकडेम एवं 10 स्टॉपडेम से 325 हेक्टेयर वास्तविक सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि हुई है। सात बड़े मिट्टी बांध के से 97. 5 हेक्टेयर, 04 तालाब से 49. 5 हेक्टेयर सिंचाई रकबा बढ़ा है। इस प्रकार कुल 373 संरचनाओं के निर्माण से कुल 1240 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि हुई है। वर्षा जल से मिट्टी का कटाव रोकने के उद्देश्य से ए। सी। टी।, बोल्डर चेक, गेबियन, गली प्लग, ब्रसवूड चेक, निर्माण से 28 हजार 320 घनमीटर जल का संरक्षण होने के साथ ही जल बहाव की गति को कम करने में मदद मिली है। जिले में नरवा विकास योजनांतर्गत वर्ष 2021-22 हेतु राजस्व क्षेत्र में नालों के उपचार के लिए 94 डीपीआर तैयार कर लिया गया है, जबकि वन क्षेत्र के नालों के उपचार के लिए 249 डीपीआर तैयार किया जा रहा है। उपचार के लिए चिन्हित 465 नालों का कुल कैचमेंट एरिया 2 लाख 45 हजार 254 हेक्टेयर है। नाला उपचार के दूसरे चरण में 5652 कार्य शामिल किए गए हैं, जिसमें से अब तक कुल 530 कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति दी जा चुकी है।

मक्का से बनेगा इथेनाल

संयंत्र की स्थापना और उत्पादन की मंजूरी

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर मंत्रिपरिषद द्वारा कोण्डागांव जिले के मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित को इथेनाल संयंत्र की स्थापना एवं उत्पादन की मंजूरी दी गई है। मक्का आधारित 80 केएलपीडी क्षमता के इस संयत्र का निर्माण कुल 135.98 करोड़ लागत से किया जायेगा। इस प्लांट में प्रतिवर्ष 63 हजार 600 मीट्रिक टन मक्के का उपयोग इथेनॉल निर्माण में किया जाएगा।

कोण्डागांव में कृषकों द्वारा रबी एवं खरीफ दोनों ही मौसमों में कुल 2 लाख 59 हजार 750 मीट्रिक टन मक्के का उत्पादन किया जाता है, जिसमें रबी सीजन में एक लाख 43 हजार 709 मीट्रिक टन एवं खरीफ सीजन में एक लाख 16 हजार 041 मीट्रिक टन मक्के का उत्पादन किया जाता है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषकों की मांग और कोण्डागांव जिले में मक्के के क्षेत्राच्छादन तथा उत्पादन को ध्यान में रखते हुए 2 जनवरी 2019 को कोण्डागांव प्रवास के दौरान जिले में मक्का प्रसंस्करण यूनिट स्थापना की घोषणा की थी, जिसका भूमिपूजन एवं शिलान्यास सांसद राहुल गांधी द्वारा बस्तर प्रवास के दौरान 16 फरवरी 2019 को किया गया था। इस प्लांट की स्थापना से क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि का आधार मजबूत होगा और मक्का उत्पादक किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मक्के का क्रय कर नियमित समय में भुगतान भी सुनिश्चित किया जाएगा। इससे क्षेत्र के 124 ग्रामीणों को प्रत्यक्ष रोजगार के साथ-साथ 65 हजार कृषकों एवं आस-पास के ग्रामीणों को अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा इथेनॉल ब्लैंडेड पेट्रोल कार्यक्रम के तहत प्रथम बार मक्के से इथेनॉल निर्माण को सम्मिलित करते हुए ब्याज अनुदान की पात्रता सूची में इसे सम्मिलित किया गया है एवं केन्द्र सरकार द्वारा मक्का आधारित इथेनॉल की दर 51. 55 रुपये प्रतिलीटर घोषित की गई है। इथेनॉल के उत्पादन से इसका विक्रय सीधे तौर पर पेट्रोलियम विक्रय करने वाली कम्पनियों को सीधे पेट्रोल के साथ प्रयोग हेतु इथेनॉल भेजा जायेगा। इसके लिये कम्पनियों द्वारा स्वयं यातायात खर्च वहन किए जाने से यातायात खर्च भी बचेगा एवं कम्पनियों द्वारा 21 दिनों में उत्पाद के भुगतान से किसानों को अपनी मेहनत का फल जल्द प्राप्त होगा। कम्पनी द्वारा भी पांच वर्षों में 87 करोड़ से अधिक का लाभ अर्जित किया जायेगा।

लघु वनोपज का कटोरा कोण्डागांव

“वनों की गोद में बसे कोण्डागांव जिले में 90 प्रतिशत से अधिक आबादी वनांचलों में निवास करती है। वनों की सघनता एवं पर्वतीय स्थल संरचना के कारण यहां मैदानी क्षेत्रों की तरह खेती संभव नहीं हो पाती है। वनों से प्राप्त होने वाले वनोत्पाद वनवासियों के जीवन का आधार और रोजगार का साधन है। कोण्डागांव जिला लघु वनोपज के उत्पादन एवं संग्रहण के कटोरे के रूप में अपनी पहचान बनाई है, जिसमें दक्षिण कोण्डागांव वनमण्डल की महत्वपूर्ण भूमिका है।”

जिला इन वनोत्पादों का संग्रहण जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, दक्षिण कोण्डागांव वनमण्डल के माध्यम से किया जा रहा है। कोण्डागांव में वनोत्पादों की प्रचुरता को देखते हुए शासन द्वारा 13 प्राथमिक लघु वनोपज समितियों के अधीन 155 ग्रामस्तर समूह तथा 31 हाट-बाजार स्तरों पर वनोपजों के संग्रहण का कार्य स्व-सहायता समूहों के माध्यम से कराया जा रहा है। इन समूहों द्वारा वर्ष 2019-20 में 21. 45 करोड़ की लागत के कुल 101260 क्विंटल लघु वनोपजों का संग्रहण किया था, जबकि लक्ष्य 56500 क्विंटल का ही रखा गया था। वर्ष 2019-20 में सामान्य परिस्थितियों के साथ जिले के संग्राहकों द्वारा उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति की गई। इस दौरान 61609 संग्राहकों द्वारा लघु वनोपज संग्रहण का कार्य किया था, वहीं 2020-21 में 51537 क्विंटल वनोपज की खरीदी की गई। वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 दोनों ही वर्षों में दक्षिण कोण्डागांव वनमण्डल लघु वनोपज उत्पादन एवं संग्रहण में प्रथम स्थान पर रहा।

वर्ष 2020-21 के शुरूवात में ही कोरोना संक्रमण का देशव्यापी प्रसार होने लगा। जिससे सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई थी। इस दौरान ग्रामीण रोजगार के सभी साधन बंद हो चुके थे। यह ऐसा दौर था, जहां छोटे-बड़े सभी व्यवसाय बंद हो गये थे। ऐसी स्थिति में नगरों में जाकर रोजगार व्यवसाय करने वाले युवा भी गांव में अपने घरों की ओर लौट गये थे। जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ही सारा भार आ गया था। ऐसे में राज्य शासन द्वारा 52

प्रकार लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी से लोगों को न सिर्फ राहत मिली, बल्कि उन्हें रोजगार और आय का अतिरिक्त जरिया भी मिला है।

ग्रामीण लॉकडाउन के दौरान गांव के आस-पास वनों में जाकर वनोत्पाद संग्रहण कार्य कर इन्हें नजदीकी वनोपज समितियों में जाकर बेचने लगे। जिससे उन्हें बाजार में व्यापारियों द्वारा औने-पौने दामों पर लघु वनोपज बेचने से राहत मिली साथ ही उन्हें अपने उत्पादों का सहीं मूल्य प्राप्त हुआ। इस दौरान जिले के 40738 संग्राहकों द्वारा 51537 क्विंटल वनोपज का संग्रहण किया गया, जिसके एवज में उन्हें 16 करोड़ रूपए की आय हुई। वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी से संग्राहकों और वन समितियों में कार्यरत महिला समूहों को भी रोजगार प्राप्त हुआ। वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 को मिलाकर वनमण्डल द्वारा संग्राहकों को कुल 37. 45 करोड़ रूपयों का भुगतान किया गया। कोरोना काल में बैंकों के बंद होने पर समूहों को विभाग द्वारा भुगतान हेतु नगद राशि प्रदान की गई थी। जिससे ग्रामीणों को सीधा लाभ प्राप्त हुआ।

इस दौरान विभाग द्वारा ईमली खरीदी का लक्ष्य 02 हजार क्विंटल तय किया गया था, जबकि संग्राहकों द्वारा 34500 क्विंटल ईमली का संग्रहण किया गया। इसके अलावा 23000 क्विंटल आटी ईमली का ग्राहकों द्वारा 34500 क्विंटल ईमली का संग्रहण किया गया। इसके अलावा 23000 क्विंटल आटी ईमली का प्रसंस्करण (डी-सिडिंग) कर फूल ईमली स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किया गया। जिसके लिये विभाग द्वारा समूहों को अतिरिक्त भुगतान भी किया गया। इस प्रकार लघु वनोपजों की आय से महामारी के दौर में भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था गतिशील और वनवासियों के चेहरों पर मुस्कान बनी रही।

गोबर से बढ़ने लगी आय

गोधन न्याय योजना से स्वालंबन की राह पर आगे बढ़ रही है महिलायें

> छत्तीसगढ़ शासन की गोधन न्याय योजना से महिलाएं आर्थिक रुप से सशक्त हो रही है। गौठान में गोबर से वर्मी खाद बनाकर उसकी बिक्री से जो लाभांश मिला उससे बिलासपुर जिले की श्रीमती माधुरी धुरी ने स्मार्ट फोन खरीदा है और इसके माध्यम से वह आधुनिक दुनिया से रूबरू हो रही है।

बिलासपुर नगर निगम अन्तर्गत मोपका के शहरी गौठान में वर्मी खाद बनाने सहित अन्य आयवर्द्धक गतिविधियों से मां अन्नपूर्णा महिला स्वसहायता समूह की सचिव श्रीमती माधुरी धुरी ने बताया कि वह विगत एक वर्ष से मोपका गौठान में अन्य महिलाओं के साथ गोधन न्याय योजना के तहत गोबर से वर्मी कम्पोस्ट बनाने का कार्य कर रही है। उसके पास पहले की-पेड वाला मोबाईल फोन था जो उसकी जरूरतो के लिए पर्याप्त नही था। वर्मी खाद की बिक्री से उसे पहली बार जब लाभांश की राशि प्राप्त हुई तो इस राशि से उसने पांच माह पहले स्मार्ट फोन खरीदा है, जिसका उपयोग कर वह अपना कार्य सुविधाजनक ढंग से कर पा रही है।

माधुरी के लगन को देखते हुए नगर निगम द्वारा उसे स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ा गया है। नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये ट्राईसाईकिल में वह कॉलोनी में जाकर घरों से कचरा संग्रहण का कार्य कर रही है। इस कार्य से उसे हर माह 6 हजार की आय मिलेगी। माधुरी सुबह जल्दी उठकर अपना घरेलु काम निपटाती है और प्रतिदिन प्रातः 7 बजे गौठान पहुंचती है फिर ट्राईसाइकिल लेकर लोगों के घरों से दोपहर तक कचरा संग्रहण करती है फिर गौठान में आकर वर्मी खाद बनाने के कार्य में जुटती है। इस तरह की व्यस्त दिनचर्या में भी वह प्रसन्न है। माधुरी पहले अपने घर तक सीमित थी। अब बाहर निकलकर सुराजी ग्राम योजना के तहत गौठान की आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी है जिससे उसमें आत्मविश्वास आ गया है और वह स्वावंलबन की राह में आगे बढ़ रही है। महात्मा गांधी जी के आदर्शों के अनुसरण में छत्तीसगढ़ सरकार की योजना ने स्वावलम्बन के उसके सपने को पूरा करने का हौसला दिया है।

बेमेतरा जिले के बेरला विकासखण्ड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सांकरा में बिहान योजना के तहत कुल बारह समूह कार्यरत है। इन समूहों में से गौठान में जुडें समूह मुख्य रूप से महिला विकास स्व-सहायता समूह संघर्ष महिला स्व-सहायता समूह, जय मां बंजारी स्व-सहायता समूह, जय मां बम्लेश्वरी स्व-सहायता समूह, और समृद्धि स्व-सहायता समूह जुडे है। महिला विकास स्व-सहायता समूह गोबर से वर्मी कम्पोस्ट का कार्य कर रहा है। यह गौठान में ही अपना कार्य संपादित करता है। इस कार्य के अलावा यह समुह फिनाईल का भी निर्माण करता है। संघर्ष महिला स्व-सहायता समुह फेब्रिक वर्क का कार्य पूरी क्षमता के साथ कर रही है, जय मां बंजारी स्व-सहायता समुह गौठान के चारागाह में बाडी का विकास का कार्य कर रही है, और मां बमलेश्वरी स्व-सहायता समूह भेड पालन का कार्य कर रही है। गौठान से जुडा हुआ समृद्धि स्व-सहयता समुह हैण्डीक्राफट का काम कर रही है। ये सारे समूह परोक्ष रूप से गौठान से जुडे हुए हैं और मल्टी-एक्टिविटी सेण्टर के रूप में विकसित होने में अपना पूरा योगदान दे रही हैं। सांकरा गौठान में 1873 क्विंटल के लगभग गोबर क्रय किया गया। इसमें 560.10 क्विंटल वर्मी खाद

ग्राम पंचायत सांकरा जनपद पंचायत बेरला से लगभग 07 कि.मी. दूर रायपुर रोड पर स्थित हैं। यहा छत्तीसगढ गोधन न्याय योजना के अंतर्गत सांकरा मे निर्मित गौठान मुख्य मार्ग से लगा हुआ हैं। इस गौठान में एक आदर्श गौठान के लिये आवश्यक सभी विशेषताएं विद्यमान है। यहां के लगभग 235 पशु पालकों के 12929 पशु है। इस गौठान मे 48 वर्मी टांका में से 4 भरे हुये है। इस गौठान में लगभग डेढ़ एकड़ रकबे में नेपियर घास, एक एकड रकबे में पैराग्रास, 2 एकड में मक्का बीज लगाया गया है, जिसमें गौठान में चारों ओर हरियाली नजर आती है। इस

का उत्पादन हुआ, जिसमें से 455.50 क्विंटल वर्मी खाद बेची गई। वर्तमान में 104 क्विंटल के लगभग वर्मी खाद शेष हैं। इस गौठान से जुडे ये समूह अपने पैरो में खडे होने की दिशा में आगे बढ रहें है। उनके चेहरों में सफलता की आभा देखी जा सकती है। वे उत्साहित होकर कहती हैं कि वे भविष्य में और भी समूहो को जोडकर मुर्गी पालन, अगरबती निर्माण, मशरूम उत्पादान और पत्तल निर्माण जैसी गतिविधियों से जोडकर इस गौठान को एक अनुकारणीय आदर्श गौठान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

गौठान में खुबसूरत बनाने के लिए दो एकड में 700 विभिन्न पोंधो का वृक्षारोपण किया गया है। मुख्य मार्ग से गुजरते हुए इस गौठान की हरियाली मन को मोह लेती है। इसे एक आदर्श गौठान के रूप में विकसित किया गया हैं। कलेक्टर श्री विलास भोसकर संदीपान ने इसे गोद लिया हैं, जिससे इसके समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसके समग्र विकास हेतु एक कार्ययोजना तैयार की गई है। इस कार्ययोजना के पूर्ण होने के पश्चात यह गौठान पूरे बेमेतरा जिले का सर्वश्रेष्ठ एवं आदर्श गौठान सह मल्टी क्वालिटी सेंटर बन जायेगा।

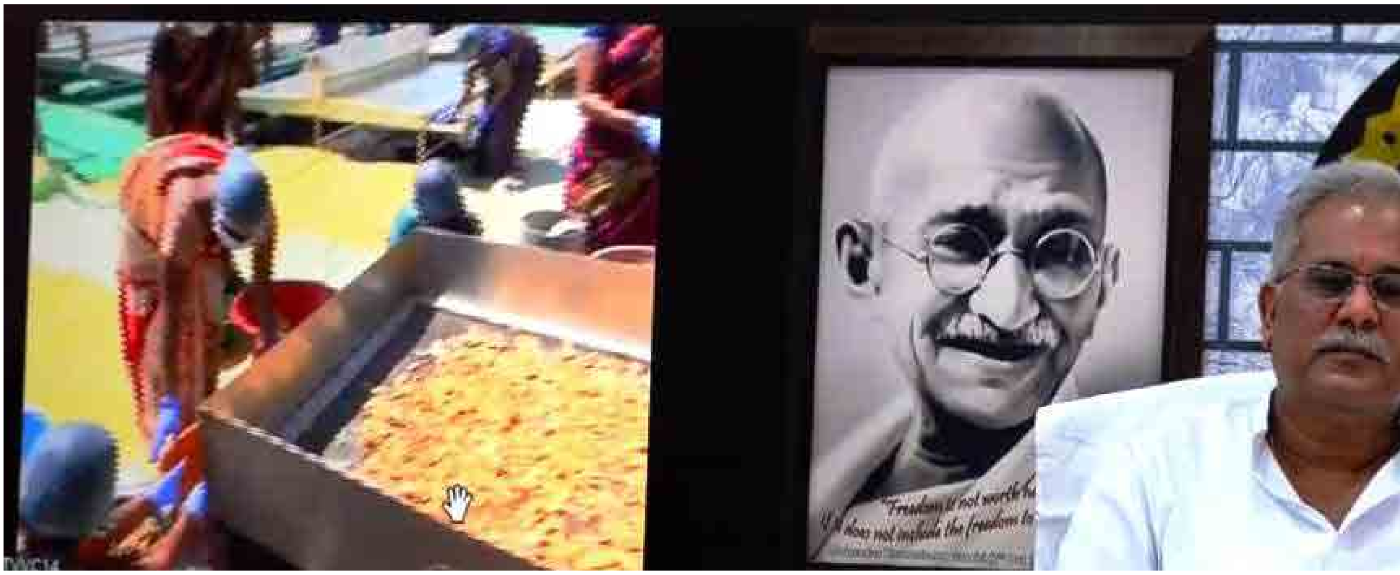

जब सीएम भूपेश से

महानायक बच्चन ने किया ये सवाल

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीति अपनाकर इन क्षेत्रों में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ-साथ विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। इससे नक्सलियों से लोगों का मोह भंग हो रहा है। नक्सल गतिविधियां अब सिमट सी गई है। इन क्षेत्रों में लोगों के जीवन में आ रहे बदलाव से यह बात स्पष्ट होती है। श्री बघेल आज एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम 12 आवर स्वस्थ्य भारत सम्पन्न भारत टेलीथॉन कार्यक्रम को बेमेतरा जिला मुख्यालय से वर्चुअल रूप से सम्बोधित कर रहे थे।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के जीवन में आ रहा है तेजी से बदलाव : मुख्यमंत्री

शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों की आय बढ़ाने पर है मुख्य फोकस

लोगों का विश्वास जीत कर उन्हें विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महानायक अमिताभ बच्चन के एक प्रश्न के जवाब में बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करने के लिए चिकित्सकों और स्टाफ की नियुक्ति की गई है। दंतेवाड़ा जिले से मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना की शुरूआत की गई थी, यह योजना राज्य के सभी जिलों में संचालित है। उन्होंने कहा कि हमने इन क्षेत्रों में विकास, विश्वास और सुरक्षा की रणनीति पर काम करना शुरू किया। इससे आम जनता तक सरकार की पहहुंच बनी। इस नीति पर अमल करते हुए हमने लोगों तक स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सोलर उर्जा से बिजली पहहुंचाने की दिशा में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रम से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लागों के जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है। बीजापुर में दिसंबर 2018 तक, जहां साल भर में एक दो टेज्क्टर की ब्रिकी होती थी आज यह आकड़ा 400 के पार पहहुंच गया है। वहीं मोटर सायकलों की ब्रिकी संख्या औसतन 15-16 से बढ़कर 5000 तक पहहुंच गई है। इन क्षेत्रों में वनअधिकार कानून का प्रभावी क्रियान्वयन कर लोगों को वनाधिकार पट्टे दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में वर्षों से बंद सैकड़ों स्कूल फिर से शुरू किए गए है। धुर नक्सल क्षेत्र जगरगुण्डा के स्कूलों में भी अब अध्ययन-अध्यापन सुचारू रूप से होने लगा है। बीजापुर के सिलगेर गांव में शासन-प्रशासन द्वारा शिविर आयोजित कर तीन हजार लोगों के आधार कार्ड, जाब कार्ड बनाने बनाए गए। उन्होंने कहा कि नक्सल गतिविधियां अब बीजापुर और नारायणपुर में सिमट कर रह गई है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करने के लिए बस्तर अंचल के सभी अस्पतालों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए। इन क्षेत्रों में लोग सप्ताह में एक बार हाट बाजार जरूर जाते हैं, इसलिए हमने लोगों की चिकित्सा का इंतजाम भी हाट बाजारों में किया। मलेरिया मुक्त अभियान चलाया इस अभियान के दौरान 14 लाख लोगों का मलेरिया के लिए रक्त परीक्षण किया गया। आज इन क्षेत्रों में मलेरिया के प्रकरण 40 प्रतिशत से घट कर 4-5 प्रतिशत रह गए है। इसके अलावा मोबाइल मेडिकल यूनिट और दाई दीदी क्लिनिक के जरिए भी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये दोनों ही योजनाएं काफी लोकप्रिय है। दाई- दीदी क्लिनिक वर्तमान में रायपुर, बिलासपुर एवं भिलाई निगम क्षेत्र में संचालित है। जल्द ही इसका विस्तार पूरे प्रदेश में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कुपोषण मुक्ति अभियान की सराहना हाल में ही नीति आयोग ने की है। राज्य में 37. 8 प्रतिशत बच्चे कुपोषण से और 41. 5 प्रतिशत महिलाएं एनिमिया से पीड़ित थी इस लिए राज्य में लोगों के लिए गरम भोजन देने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चलाया जा रहा है। पिछले एक साल में कुपोषण के मामले में उल्लेखनीय कमी आयी है। इसी प्रकार स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए लोगों को जागरूक करने की पहल के सार्थक परिणाम देखने को मिल रहा है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ आने वाले समय में देश का मिलेट हब बनेगा। उन्होंने कहा कि मिलेट मिशन के तहत किसानों को लघु धान्य फसलों की सही कीमत दिलाने आदान सहायता देने, खरीदी की व्यवस्था, प्रोसेसिंग और विशेषज्ञों की विशेषज्ञता का लाभ दिलाने की पहल की है। हम लघु वनोपजों की तरह लघु धान्य फसलों को भी छत्तीसगढ़ की ताकत बनाना चाहते हैं।

छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन का हुआ शुभारंभ

कोदो, कुटकी एवं रागी की उत्पादकता बढ़ाने इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद और 14 जिलों के मध्य एमओयू

आई. आई. एम. आर. किसानों को देगा तकनीकी जानकारी, उच्च क्वालिटी के बीज, सीड बैंक की स्थापना में मदद और प्रशिक्षण

राज्य सरकार द्वारा आदान सहायता, समर्थन मूल्य पर खरीदी, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की विशेष पहल

मिलेट के प्रसंस्करण और वेल्यूएडिशन से किसानों, महिला समूहों और युवाओं को मिलेगा रोजगार

छत्तीसगढ़ बनेगा देश का मिलेट हब

कोदो और कुटकी

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कार्यालय में इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद और राज्य के मिलेट मिशन के अंतर्गत आने वाले 14 जिलों कांकेर, कोण्डागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, राजनांदगांव, कवर्धा, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर और जशपुर के कलेक्टरों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर के लिए आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। एमओयू के अंतर्गत इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी एवं रागी की उत्पादकता बढ़ाने, तकनीकी जानकारी, उच्च क्वालिटी के बीज की उपलब्धता और सीड बैंक की स्थापना के लिए सहयोग और मार्गदर्शन देगा। इसके अलावा आईआईएमआर हैदराबाद द्वारा मिलेट उत्पादन के जुड़ी राष्ट्रीय स्तर पर विकसित की गई वैज्ञानिक तकनीक का मैदानी स्तर पर प्रसार हेतु छत्तीसगढ़ के किसानों को कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। 14 जिलों के कलेक्टर कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े। देश-विदेश में कोदो-कुटकी, रागी जैसे मिलेट की बढ़ती मांग को देखते हुए

10 हजार रूपए प्रति एकड़ आदान सहायता दी जाएगी

श्री बघेल ने कहा कि लघु धान्य फसलों की खरीदी छत्तीसगढ़ लघु वनोपज सहकारी संघ की वन-धन समितियों के माध्यम से किया जाएगा। इन फसलों की प्रोसेसिंग करके इनका उपयोग मध्यान्ह भोजन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पोषण आहर कार्यक्रम जैसी योजनाओं में होगा। इनसे तैयार उत्पादों को महानगरों के बाजारों तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मिलेट मिशन के आगामी 05 वर्षों के लिए 170 करोड़ 30 लाख रुपए का प्रबंधन डीएमएफ एवं अन्य माध्यमों से किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि मिलेट मिशन के अंतर्गत कोदो-कुटकी और रागी की फसल लेने वाले किसानों को 9 हजार रुपए प्रति एकड़ तथा धान के बदले कोदो-कुटकी और रागी लेने पर 10 हजार रूपए प्रति एकड़ आदान सहायता दी जाएगी।

मिलेट मिशन से वनांचल और आदिवासी क्षेत्र के किसानों की न केवल आमदनी बढ़ेगी, बल्कि छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान मिलेगी। वहीं मिलेट्स के प्रसंस्करण और वेल्यूएडिशन से किसानों, महिला समूहों और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। छत्तीसगढ़ के 20 जिलों में कोदो-कुटकी, रागी का उत्पादन होता है। प्रथम चरण में इनमें से 14 जिलों के साथ एमओयू किया गया।

100 लोगों को रोजगार मिलेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि लघु वनोपजों की तरह लघु-धान्य-फसलों के वैल्यू एडीशन से स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। कांकेर और दुगूकोंदल में दो प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित हो चुकी है। स्व सहायता समूहों की बहनों को इससे रोजगार मिल रहा है। लघु-वनोपजों की तरह लघु धान्य फसलों को भी हम छत्तीसगढ़ की नयी ताकत बनाना चाहते हैं। अगले चरण में ऐसे और भी जिलों के साथ एमओयू किए जाएंगे, जहां कोदो, कुटकी, रागी का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है।

कार्यक्रम में कांकेर जिले में मिलेट प्रोसेसिंग उद्योग स्थापित करने के लिए अवनि आयुवेर्दा प्राइवेट लिमिटेड तथा महुआ प्रसंस्करण के लिए मेसर्स ब्रज कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड और उद्योग विभाग के मध्य एमओयू किया गया।

फसलें पोषण से भरपूर

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर कहा कि कोदो, कुटकी और रागी जैसी लघु धान्य फसलें ज्यादातर हमारे वनक्षेत्रों में बोई जाती हैं। कोदो, कुटकी और रागी जैसी फसलें पोषण से भरपूर हैं। देश में इनकी अच्छी मांग है। शहरी क्षेत्रों में बहुत अच्छी कीमत पर ये बिकती हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में पैदा होने वाली कोदो, कुटकी और रागी वनांचल से बाहर निकल ही नहीं पाई है। अभी तक इन फसलों का न तो समर्थन मूल्य तय था, और न ही इसकी खरीदी की कोई व्यवस्था थी। इतनी महत्वपूर्ण और कीमती फसल उपजाने के बाद भी इसे उपजाने वाले किसान गरीब के गरीब रह गए।

कांकेर जिले में कोदो-कुटकी और रागी वेल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग के लिए अवनि आयुवेर्दा द्वारा 5. 34 करोड़ रूपए की लागत से प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। इस प्रोसेसिंग प्लांट की क्षमता लगभग 5 हजार टन प्रतिवर्ष होगी। इसमें लगभग 100 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी प्रकार महुआ प्रसंस्करण के लिए मेसर्स ब्रज कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 25 करोड़ रूपए की लागत से प्लांट लगाया जाएगा, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से 75 लोगों को रोजगार मिलेगा।

आई. आई. एम. आर. के डायरेक्टर डॉ। विलास ए। तोनापी ने कहा कि

सीड बैंक स्थापित किए जाएंगे

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के प्रबंध संचालक संजय शुक्ला ने कहा कि आई. आई. एम. आर. द्वारा जिलों में विशेषज्ञ तैनात किए जाएंगे जो किसानों को मिलेट का उत्पादन बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन देंगे। राज्य स्तर पर भी सीनियर कंसलटेंट नियुक्त किया जाएगा। ये मास्टर टेज्नर के रूप में काम करेंगे। उन्होंने बताया कि बस्तर, सरगुजा, कवर्धा और राजनांदगांव में लघु धान्य फसलों के सीड बैंक स्थापित किए जाएंगे।

वर्तमान समय में लाईफ स्टाईल डिजिजेस और कुपोषण जैसी समस्या के निदान के लिए हमारे भोजन में फूड डायवर्सिटी बढ़ाने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में शुरू हो रहा मिलेट मिशन इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेट की पैदावार लेने वाले किसानों को राज्य सरकार द्वारा आदान सहायता उपलब्ध कराना एक अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मनाया जाएगा। मिलेट मिशन के माध्यम से वर्ष 2023 तक छत्तीसगढ़ देश में मिलेट हब के रूप में पहचान बनाने में सफल होगा।

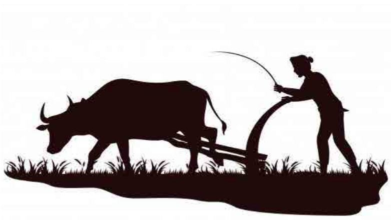

किसानों की तरह आदान सहायता मिल सकेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अब इन फसलों की पैदावार बढ़ाने, इनकी खरीदी की अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करने और इनकी प्रोसेसिंग कर इन्हें शहर के बाजारों तक पहुंचाने के लिए मिशन-मिलेट शुरू किया है। राज्य सरकार ने कोदो, कुटकी और रागी का समर्थन मूल्य तय करने के साथ-साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में इन्हें भी शामिल किया है। इससे अब इन लघु धान्य फसलों को उपजाने वाले किसानों को भी अन्य किसानों की तरह आदान सहायता मिल सकेगी।

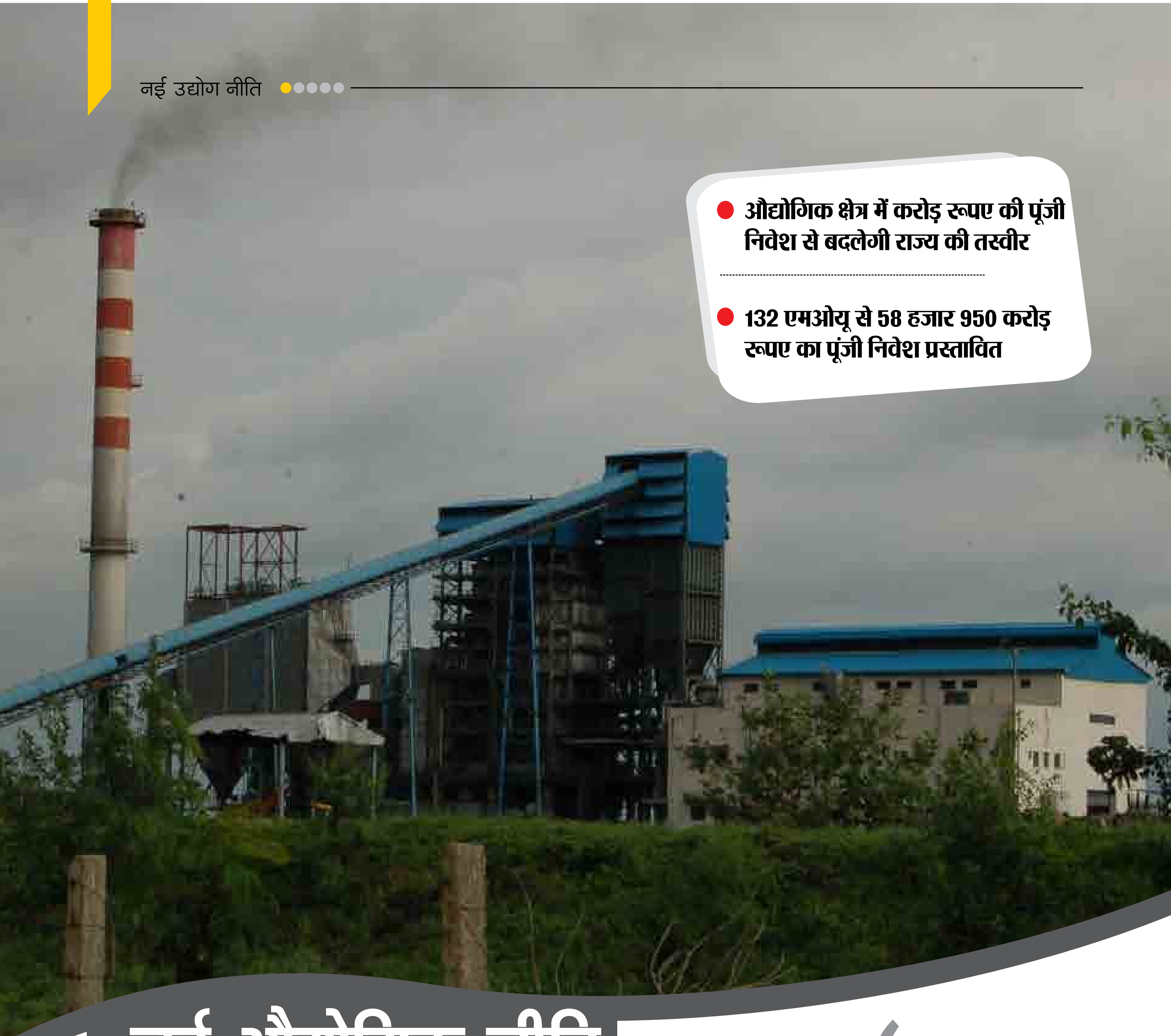

- औद्योगिक क्षेत्र में करोड़ रूपए की पूंजी निवेश से बदलेगी राज्य की तस्वीर
- 132 एमओयू से 58 हजार 950 करोड़ रूपए का पूंजी निवेश प्रस्तावित

नई औद्योगिक नीति से राज्य में बना नया औद्योगिक वातावरण

“मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा औद्योगिक विकास को गति देने के लिए किए गए दूरदर्शिता पूर्ण निर्णय का परिणाम आज देखने को मिलने लगा है। पिछले ढ़ाई सालों में राज्य में 1564 नई औद्योगिक इकाईयां स्थापित हुई हैं, जिसमें 18 हजार 882 करोड़ रूपए से अधिक का पूंजी निवेश हुआ है।”

इससे 30 हजार से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होने के साथ ही राज्य के औद्योगिक विकास में तेजी आएगी। राज्य की नई औद्योगिक नीति 2019 से 2024 तक लागू की गई है। नवीन औद्योगिक नीति से नये औद्योगिक और आर्थिक वातावरण का निर्माण हुआ है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने नयी उद्योग नीति का निर्माण कर कृषि और वन आधारित उद्योगों को प्राथमिकता देने के साथ-साथ निवेश के लिए अनुकूल वातावरण के निर्माण के लिए विशेष पैकेज और रियायतें दी हैं। इसके साथ ही उद्योगों की स्थापना तथा संचालन के नियमों का भी सरलीकरण किया है। प्रदेश में 1 जनवरी 2019 से 23 अगस्त 2021 तक नये उद्योग की स्थापना के लिए 132 एमओयू किए गए हैं, जिसमें 58 हजार 950 करोड़ रूपए का पूंजी निवेश प्रस्तावित है। इससे 78 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें कोर सेक्टर के साथ एथेनाल, फूड सेक्टर, फार्मास्युटिकल, इलेक्ट्रानिकल, डिफेंस, सोलर आदि क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल हैं। वर्तमान में राज्य की महत्वाकांक्षी औद्योगिक परियोजना बायो एथेनाल संयत्र की स्थापना के लिए 13 एमओयू किए गए हैं, जिसमें 2 हजार 202 करोड़ रूपए का पूंजी निवेश प्रस्तावित है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ का आयोजन 27 जनवरी 2022 से 1 फरवरी 2022 तक किया जाएगा। इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ के आयोजन के माध्यम से राज्य में 50 बिलियन डॉलर से अधिक वैश्विक निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

छत्तीसगढ़ में आयोजित की जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के माध्यम से विश्व के प्रमुख निवेशक समुदायों, कंपनियों, बिजनेस लीडर एवं राज्य सरकार के अधिकारी तथा स्थानीय उद्योगपतियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा। इससे राज्य के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में शामिल होने वाले निवेशक समुदायों और वैश्विक कम्पनियों को छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं और इससे मिलने वाले लाभ, राज्य सरकार की नीति, प्रक्रिया, नियमों की जानकारी देने के साथ उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया जाएगा।

RAMKRISHNA
CARE
HOSPITALS

- दुर्घटना और आपातकाल
- क्रिटिकल केयर
- जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी
- बोन और ज्वाइंट
- डरमेटोलॉजी और कॉस्मेटोलॉजी
- जनरल मेडिसीन
- कैंसर केयर
- ईएनटी
- न्यूरो साइंसेस
- कार्डियक साइंसेस
- गैस्ट्रो और जीआई सर्जरी
- पीडियाट्रिक्स
- प्लास्टिक सर्जरी
- पलमोनोलॉजी
- रीनल साइंसेस
- वुमन्स हेल्थ

श्रेष्ठता, विश्वसनीयता और भरोसे का प्रतीक

रामकृष्ण केयर अस्पताल

पचपेड़ी नाका, धमतरी रोड, रायपुर (छ.ग.)

अपॉइंटमेंट के लिए : 07716165656 • इमरजेंसी के लिए : 1800 843 0000

AdPRAYAS

स्वालंबन की राह पर चल पड़ी माधुरी

खाद की कमाई से खरीदी स्मार्ट फोन

माधुरी धुरी के जीवन की धुरी पहले उसके घर एवं परिवार तक सीमित थी। बाहरी दुनिया से उसका नाता नही था लेकिन जब से उसे गौठान में स्वसहायता समूह से जुड़कर कार्य करने का मौका मिला उसकी तो दुनिया ही बदल गई है। गौठान में गोबर से वर्मी खाद बनाकर उसकी बिक्री से जो लाभांश मिला उससे माधुरी ने स्मार्ट फोन खरीदा है। और इसके माध्यम से वह आधुनिक दुनिया से रूबरू हो रही है।

बिलासपुर नगर निगम अन्तर्गत मोपका के शहरी गौठान में वर्मी खाद बनाने सहित अन्य आयवर्द्धक गतिविधियों में रत मां अन्नपूर्णा महिला स्वसहायता समूह की सचिव श्रीमती माधुरी धुरी ने बताया कि वह विगत एक वर्ष से मोपका गौठान में अन्य महिलाओं के साथ गोधन न्याय योजना के तहत गोबर से वर्मी कम्पोस्ट बनाने का कार्य कर रही है। उसके पास पहले की-पेड वाला मोबाईल फोन था जो उसकी जरूरतो के लिए पर्याप्त नही था। वर्मी खाद की बिक्री से उसे पहली बार जब लाभांश की राशि प्राप्त हुई तो इस राशि से उसने पांच माह पहले स्मार्ट फोन खरीदा है। जिसका उपयोग कर वह अपना कार्य सुविधाजनक ढंग से कर पा रही है।

माधुरी के लगन को देखते हुए नगर निगम द्वारा उसे स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ा गया है। नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये ट्राईसाईकिल में वह कॉलोनी में जाकर घरों से कचरा संग्रहण का कार्य कर रही है। जिससे उसे हर माह 6 हजार की आय मिलेगी। माधुरी सुबह जल्दी उठकर अपना घरेलु काम निपटाती है और प्रतिदिन प्रातः 7 बजे गौठान पहुंचती है फिर ट्राईसाइकिल लेकर लोगों के घरों से दोपहर तक कचरा संग्रहण करती है फिर गौठान में आकर वर्मी खाद बनाने के कार्य में जुटती है। इस तरह की व्यस्त दिनचर्या में भी वह प्रसन्न है।

माधुरी पहले अपने घर तक सीमित थी। अब बाहर निकलकर सुराजी ग्राम योजना के तहत गौठान कि आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी है जिससे उसमें आत्मविश्वास आ गया है और वह आत्मनिर्भर बनकर स्वावंलबन की राह में आगे बढ़ रही है।

विकास का छत्तीसगढ़ मॉडल

जिला स्तर पर विशेष रणनीति से विकास की नई राह पर की बात

महिला स्व-सहायता समूहों ने ई-कॉमर्स पर बेची 22 हजार 480 राखियां

स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने में जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका

असम की तरह जशपुर जिले में दिखने लगे हैं चाय के बागान

कुपोषित बच्चों की संख्या में 32 प्रतिशत की कमी

"मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि स्थानीय टैलेंट, स्थानीय युवा और स्थानीय संसाधनों के उपयोग से हम विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल को और ज्यादा विस्तार देंगे।"

इससे छत्तीसगढ़ का हर क्षेत्र समृद्ध और खुशहाल होगा। मुख्यमंत्री प्रसारित मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की 22 वीं कड़ी में जनता से 'जिला स्तर पर विशेष रणनीति से विकास की नई राह' विषय पर बातचीत कर रहे थे। इस विषय पर यह लोकवाणी की दूसरी कड़ी है। मुख्यमंत्री की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी का प्रसारण आज आकाशवाणी के सभी केन्द्रों, एफ.एम. रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों में किया गया। बघेल ने कहा कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने में जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डीएमएफ एवं मनरेगा से इसमें काफी मदद की जा सकती है। स्थानीय मौसम, मिट्टी और विशेषता को देखते हुए जिस तरह बीजापुर में मिर्ची की खेती का सपना साकार हो रहा है। वैसे ही अन्य जिलों में भी वहां की विशेषता के अनुसार बहुत से काम हो रहे हैं और इसमें बहुत बढ़ोत्तरी करने की संभावना है। जिला प्रशासन की पहल से अब जशपुर जिले में असम की तरह चाय के बागान दिखने लगे हैं। अबूझमाड़ में लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके इसके लिए गांवों का सर्वे कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ी भाषा में अपने उद्‌बोधन की शुरूआत करते हुए प्रदेशवासियों को नवरात्रि, दशहरा, करवा चौथ, देवारी, गौरा-गौरी पूजा, मातर, गोवर्धन पूजा, छठ पर्व, भाई-दूज आदि त्यौहारों की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के चारों कोनो में देवी माई के बड़े-बड़े मंदिर है। दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी दाई, डोंगरगढ़ में बम्लेश्वरी दाई, रतनपुर में महामाया दाई, चंद्रपुर में चंद्रहासिनी दाई बिराजी हैं। नारी शक्ति के रूप में हम बेटियों की पूजा करते हैं और हमारे यहां कन्या भोज कराने की भी परंपरा है। उन्होंने कहा कि बेटियों और नारियों के प्रति सम्मान भाव के कारण हमारे यहां वर्ष में दो बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। बेटियों और नारियों के प्रति सम्मान का यह भाव हमें पूरी जिंदगी निभाना है। यहीं सही मायने में छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा है। हमें अपनी परंपरा और संस्कृति की शिक्षा से अपने जीवन में उतारना है। राज्य सरकार ने दाई-दीदी के अधिकार और उनके मान-सम्मान को बढ़ाने का प्रयास किया है।

नारायणपुर जिले के 19 ग्रामों का प्रारंभिक नक्शा एवं अभिलेख तैयार

बघेल ने कहा कि अबूझमाड़ को ठीक ढंग से बूझने की दिशा में हमने ठोस कार्यवाही शुरू कर दी है। जल्दी ही इसका लाभ जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगेगा। लोकवाणी में अबूझमाड़ के नारायणपुर जिले के श्री सत्यनारायण ने बताया कि अबूझमाड़ क्षेत्र में राजस्व भूमि के सर्वे के बाद गांवों के लोगों की जमीन का पट्टा बन गया है। अब वे लोग धान बेच रहे हैं। भूमि का समतलीकरण किया गया है और उन्हें राज्य शासन की अन्य योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। उन्होंने इसके लिए ग्रामवासियों की ओर से मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस संबंध में कहा कि अबूझमाड़ का मतलब ऐसा वन क्षेत्र जिसे

नरवा योजना में 30 हजार नालों में होंगे जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की नरवा योजना के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि नरवा योजना के तहत प्रदेश के 30 हजार नालों में जल संरक्षण और संवर्धन का कार्य करने की शुरूआत की गई है। जिससे किसानों को पानी की चिंता से छुटकारा मिले। लोकवाणी में कोरबा जिले के ग्राम लबेद के श्री टीकाराम राठिया ने बताया था कि उनके गांव के नाले पर बने बांध से अब लगभग साढ़े तीन सौ एकड़ में किसान धान और साग-सब्जी की खेती कर रहे हैं। बघेल ने कहा कि लबेद गांव में 25 साल पहले मिट्टी का बांध बनाकर पानी रोका गया था। जिला प्रशासन ने अच्छी पहल करते हुए 2 करोड़ 34 लाख रूपए की लागत से इस बांध का वैज्ञानिक ढंग से पुनरोद्धार और नवनिर्माण का कार्य कराया, जिससे इस बांध की सिंचाई क्षमता दोगुनी हो गई है। पहले जहां 210 एकड़ में पानी पहुंच पाता था, अब 419 एकड़ तक पानी पहुंच रहा है। लबेद और गिद्धकुंवारी के लोगों को इसका लाभ मिलने लगा है। इस बांध से लगी 800 मीटर की अंडर ग्राउंड नगर बनाई गई है। जिससे पानी अंतिम छोर तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि लबेद जलाशय परियोजना की सफलता से अन्य जिलों के लोगों को प्रेरणा मिलेगी।

बूझा नहीं जा सकता।

जब हमारी सरकार आई मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रदेश का कोई क्षेत्र अबूझा रह जाए, जहां की आशाओं को समझने जनसुविधाओं और विकास की योजनाओं को पहुंचाने की कोई व्यवस्था ही न हो। उन्होंने कहा कि जब जांच कराई गई तो पता चला कि नारायणपुर जिले के ओरछा विकासखण्ड के 237 गांव और नारायणपुर विकासखंड के 9 गांव असर्वेक्षित हैं। जिसके कारण किसानों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक ओरछा विकासखण्ड के चार तथा नारायणपुर विकासखण्ड के 9 गांवों का प्रारंभिक सर्वे पूर्ण कर उन्हें भुईयां साफ्टवेयर के साथ जोड़ा गया है तथा छह अन्य ग्रामों का सर्वेक्षण कार्य प्रक्रिया में है। आईआईटी रूड़की के सहयोग से 19 ग्रामों का प्रारंभिक नक्शा एवं अभिलेख तैयार कराया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि सर्वेक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रारंभिक अभिलेख अथवा मसाहती खसरा को आधार बनाकर कब्जेदार को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाए। ओरछा विकासखण्ड से 1 हजार 92 तथा नारायणपुर विकासखण्ड से 1 हजार 842 ग्रामीणों ने विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन दिए हैं। इन आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए पात्र हितग्राहियों को लाभ दिया जा रहा है।

जशपुर में चाय के बागान तैयार

बघेल ने जशपुर जिले में चाय की खेती से ग्रामीणों को मिल रहे लाभ का जिक्र करते हुए कहा कि असम की तरह अब जशपुर में भी चाय के बगान दिखने लगे हैं। इसके पीछे स्थानीय समुदाय की ताकत है। जशपुर जिले के चाय के बागान लोगों की आय का बड़ा जरिया बनेंगे। जशपुर विकासखण्ड के सारूडीह गांव में चाय की खेती हो रही है। लोकवाणी में जशपुर निवासी अशोक तिर्की ने मुख्यमंत्री से जानना चाहा कि जशपुर में चाय की खेती सफल हो सकती है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कहा कि संयुक्त वन प्रबंधन समिति सारूडीह के अंतर्गत स्व-सहायता समूह के अनुसूचित जनजाति के 16 परिवारों के सदस्यों से मिला जा सकता है, जिन्होंने जिला प्रशासन के मार्गदर्शन और अपनी मेहनत से 20 एकड़ क्षेत्र को चाय के बागान में बदल दिया है। यहां 20 एकड़ कृषि भूमि पर चाय का रोपण किया गया है। चाय रोपण के प्रबंधन एवं प्रसंस्करण में 2 महिला स्व-सहायता समूह जुड़े हैं। अब तो चाय रोपण से व्यापारिक स्तर पर ग्रीन टी एवं सी.टी.सी.टी का निर्माण किया जा रहा है। यहां निर्मित चाय की गुणवत्ता की जांच भी व्यावसायिक संस्थाओं से कराई गई है, जिसमें दोनों प्रकार की चाय को उत्तम गुणवत्ता का होना पाया गया है। इस चाय बागान में जैविक खेती को ही आधार बनाया गया है। इसके लिए हितग्राही परिवारों को उन्नत नस्ल का पशुधन भी उपलब्ध कराया गया है, जिससे उनको अतिरिक्त लाभ हो रहा है। इसी तरह मनोरा ब्लॉक में कांसाबेल, जशपुर ब्लॉक में बालाछापर और गुटरी में भी 60 एकड़ रकबे में चाय के बागान तैयार हो गए हैं।

डीएमएफ मद के सदुपयोग के चमत्कारिक नतीजे

कबीरधाम जिले के श्री बंसत यादव ने डीएमएफ मद से किए जा रहे कार्यों की सफलता के बारे में मुख्यमंत्री से जानना चाहा। उन्होंने बताया कि कबीरधाम जिले में डीएमएफ मद से शिक्षित युवाओं को शाला संगवारी के रूप में रोजगार दिया जा रहा है। बाइक एम्बुलेंस तथा सुपोषण अभियान जैसे कामों में मदद की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीएमएफ की राशि वास्तव में उन क्षेत्रों की अमानत है, जहां खनन गतिविधियों के कारण पर्यावरण, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षण, पोषण आदि गतिविधियों पर असर पड़ता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने डीएमएफ की राशि के उपयोग के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए, जिससे इस राशि का उपयोग वास्तव में खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के विकास में, पुनर्वास में हो सके। श्री बघेल ने कहा कि इस मद की राशि से कबीरधाम जिले में 100 से अधिक शिक्षित युवाओं को शाला संगवारी के रूप में रोजगार दिया जा रहा है। ग्रामीण और वन क्षेत्रों में संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में द्वितीय एएनएम के रूप में 80 से अधिक स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। साथ ही डीएमएफ के माध्यम से बड़ी राशि अधोसंरचना विकास के लिए दी गई है। जिला अस्पताल को अपग्रेड किया जा रहा है। विशेषज्ञ चिकित्सकों और हेल्थ स्टाफ की नियुक्ति की गई है। वन क्षेत्रों में बाईक एम्बुलेंस गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। कबीरधाम जिले में मातृत्व स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत सुरक्षित संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा संचालित हो रही है। वन क्षेत्रों-जैसे दलदली, बोक्करखार, झलमला, कुकदूर, छीरपानी में इसका अच्छा असर हुआ है। इससे 2 हजार से अधिक गर्भवती माताओं को संस्थागत प्रसव कराने और उन्हें सुरक्षित घर छोड़ने में मदद मिली है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान में डीएमएफ की राशि का उपयोग काफी कारगर साबित हुआ है। कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त पौष्टिक आहार अंडा और केला देने की शुरूआत की गई। 1 से 3 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों में गर्म भोजन दिया जा रहा है। जिले में 2019 के वजन तिहार के मुकाबले, वर्ष 2021 में कुपोषण की दर 19.56 प्रतिशत से घटकर 13 प्रतिशत हो गई है। यह एक बड़ी उपलब्धि है।

जिलों में जनसमस्या निवारण की सुविधाजनक प्रणाली विकसित करें

सूरजपुर जिले की गुरुचंदा ठाकुर ने सूरजपुर जिले में जनसमस्याओं के निवारण के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रारंभ किए गए जन संवाद कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी और गांव के अनेक लोगों की अनेक समस्याओं का समाधान इस नई व्यवस्था से हुआ है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कहा कि जिला स्तर पर की गई इस पहल का लाभ लोगों को मिल रहा है। आदिवासी अंचल और वन क्षेत्र होने के कारण आवागमन की दिक्कत भी है। जिसके कारण लोगों को सरकारी ऑफिस में पहुंचना कठिन होता है। सूरजपुर जिले में जन संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत कॉल सेंटर के माध्यम से जिला मुख्यालय में सभी विकासखण्ड मुख्यालयों की समस्याएं सुनी जाती हैं। फोन रिसीव किए जाते हैं और आवेदन की कापी व्हाट्सअप पर ली जाती है। ज्यादातर मामलों में 24 घंटे के भीतर समस्या का समाधान हो जाता है। कॉल सेंटर के माध्यम से राजस्व संबंधी सीमांकन, बटांकन, ऋण पुस्तिका, ऑनलाईन रिकार्ड आदि सारे काम हो रहे हैं। किसी को पेंशन में समस्या है, राशन कार्ड बनवाना है, नाम जुड़वाना है, सड़क, नाली, पुल-पुलिया, सामुदायिक भवन आदि की मांग है। पीडीएस दुकान, स्वास्थ्य केन्द्र के बारे में कुछ कहना है, जनपद में निर्माण संबंधी कार्यों के प्रस्ताव हों या भुगतान की समस्या। बिजली आपूर्ति को लेकर कोई शिकायत है। ऐसे सभी मामले इस प्रणाली से हल हो रहे हैं। मुझे खुशी है कि इस व्यवस्था से संतुष्ट लोग फोन करके जानकारी भी दे रहे हैं। इसीलिए मैंने पूरे प्रदेश में जिला प्रशासन को खुली छूट दी है कि वे मौलिक तरीके से या स्थानीय जरूरतों और विशेषताओं के अनुसार जनसमस्या निवारण की अपनी प्रणाली विकसित करें। ऐसे नवाचारों का खूब स्वागत है।

ऐसी ही रिपोर्ट हर जिले से मिल रही है। जिसके कारण प्रदेश में कुपोषित बच्चों की संख्या में 32 प्रतिशत की कमी आई है। हमें नई सोच और नए उपायों से छत्तीसगढ़ को पूर्णतः कुपोषण मुक्त राज्य बनाना है।

बीजापुर जिले के किसान मिर्ची की खेती से प्रति एकड़ कमाएंगे डेढ़ लाख रूपए

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधन उपलब्ध कराने और लोगों को आर्थिक मदद देने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का लोकवाणी में उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में खेती-किसानी और परंपरागत रोजगार के अवसरों को मजबूत करने के अनेक उपाए किए जा रहे हैं जिससे लोगों को आर्थिक मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, गोधन न्याय योजना, वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी, लघु धान्य फसलें जिन्हें मिलेट्स कहा जाता है उनके उत्पादन और प्रसंस्करण की व्यवस्था, सिंचाई के लिए निःशुल्क पानी की व्यवस्था, कृषि ऋण माफी, सिंचाई कर माफी, पौनी-पसारी योजना जैसे अनेक कामों से गांव वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। हम हर समस्या का समाधान चाहते हैं। बीजापुर जिले के चंदूर गांव के श्री देवर किष्टैया ने लोक वाणी में रिकॉर्ड किए गए संदेश के माध्यम से बताया कि गांव में बारहमासी रोजगार के अवसर नहीं होने के कारण अनेक ग्रामीण नदी पार तेलंगाना मिर्ची के खेतों में मिर्ची तोड़ाई के लिए जाते थे, लेकिन बचत नहीं हो पाती थी। नई सरकार आने के बाद जिला प्रशासन द्वारा मिर्ची की खेती के लिए दिए गए सहयोग से अब चंदूर तथा पड़ोसी गांव कोत्तूर और तारलागुड़ा में मिर्ची की खेती की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा बीज खाद, पंप, नलकूप, ड्रिप सिस्टम, मल्चिंग, विद्युत एवं फेंसिंग जैसी मूलभूत सुविधाएं निःशुल्क प्रदाय की गई है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजापुर जिले के चंदूर, तारलागुड़ा और कोत्तूर गांव में जिला प्रशासन द्वारा मिर्ची की खेती की जो पहल की गई है। इससे इन तीन गांवों में 155 एकड़ जमीन के स्वामी 78 किसान परिवारों को मिर्ची की खेती के लिए तैयार किया गया है। डीएमएफ एवं मनरेगा के माध्यम से खेतों की फेंसिंग, बीज, खाद, बोर, ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग एवं विद्युत आदि प्रारंभिक व्यवस्था करके नर्सरी तैयार कर ली गई है। इस तरह जो लोग पहले मूंग की खेती करके प्रति एकड़ लगभग 10 हजार रुपए कमाते थे, वे मिर्ची की खेती करके, एक से डेढ़ लाख रुपए तक प्रति एकड़ कमाएंगे। इसके अलावा मिर्ची तोड़ने के काम में स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार, बेहतर रोजी और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी, जिससे वे अपने गांव, अपने घर और अपने परिवार में रहते हुए काफी राशि बचा सकेंगे।

महिला समूहों का 13 करोड़ रूपए का कालातीत ऋण माफ

राजनांदगांव जिले के ग्राम मनगटा के प्रियंबिका स्व-सहायता समूह की सुश्री रामेश्वरी साहू ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वे स्वयं गौठान में वर्मी कम्पोस्ट के निर्माण सहित विभिन्न गतिविधियों से जुड़ी है। उनके गांव की 28 समूहों की 50 दीदियों ने रक्षा बंधन पर्व पर धान, बीज, गेहूं, चावल, बांस की राखियों का निर्माण किया था। ई-कॉमर्स पर लगभग दो लाख 30 हजार से अधिक राशि की 25 हजार से अधिक राखियों का देश-विदेश में ऑनलाईन व ऑफलाईन विक्रय किया गया। उन्होंने बताया कि हम लोगों द्वारा बनाई गई राखी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने अमेजान से मंगाकर आपको बांधी थी। उन्होंने कहा कि हम लोग द्वारा बनाई राखी पहनकर आपने हमारा मान-सम्मान बढ़ाया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में महिला स्व-सहायता समूहों को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाएं गए हैं। हमारी बहनों ने भी रोजगार मूलक कार्यों में दिलचस्पी दिखाई है। इसके साथ-साथ ही अपने गांव की सुरक्षा और कुरीतियों के खिलाफ जंग छेड़ने के साथ समूह की महिलाओं ने अनेक नवाचार किए हैं और अपने परिवार को स्वावलंबी बनाया है।

राज्य के कई इलाकों में अल्प वर्षा के चलते खरीफ फसलों को सूखने से बचाने में सोलर पंप संजीवनी साबित हो रहे है। सरकार की सौर सुजला योजना के अंतर्गत सुदूर ग्रामीण एवं वनांचल के किसानों के लिए क्रेडा द्वारा स्थापित सोलर पंप फसलों की सिंचाई के लिए भरपूर काम आ रहे हैं। सौर सुजला योजना लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए एक सफल योजना है। गरियाबंद जिले में सौर सुजला योजना के तहत अभी तक कुल 7025 सोलर पंप स्थापित किए जा चुके है। उल्लेखनीय है कि गरियाबंद जिले में सौर सुजला योजना के प्रथम चरण से लेकर चतुर्थ चरण तक 5860 सोलर पंपों की स्थापना की गई है। सोलर पंपों की स्थापना की दृष्टि से गरियाबंद जिला अग्रणी है। जिले में सौर सुजला योजना के पंचम चरण में 2000 पंप स्थापना के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 1235 पंप स्थापित किए जा चुके है। शेष पंपों की स्थापना का काम जारी है।

सोलर पंप बने फसलों के लिए संजीवनी

सौर सुजला योजना के तहत विद्युतविहीन एवं दूरस्थ ग्रामों के किसानों को कृषि कार्य हेतु 95 प्रतिशत तक अनुदान में 2. 5 लाख से 4. 5 लाख रुपए लागत मूल्य के सोलर पंपों को मात्र 10 हजार से 21 हजार रुपए में प्रदान किया जा रहा है। पहले किसानों के पास सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं होने पर वे पूर्ण रूप से फसलों की सिंचाई के लिये वर्षा पर निर्भर रहते थे। बारिश नहीं होने या अल्प वर्षा की स्थिति में किसानों की फसल खराब हो जाती थी, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान होता था। वर्तमान में सौर सुजला योजना ने किसानों को काफी राहत दी है। इस योजना से स्थापित सोलर पंप के कारण अब किसानों को बारिश पर निर्भर नहीं होना पडता है तथा सिचाई की सुविधा मिल जाने से अब पैदावार भी बेहतर होने लगी है। सौर सुजला योजना के तहत लाभान्वित किसानों की आर्थिक स्थिति में लगातार सुधार आ रहा है।

विकासखण्ड मैनपुर के ग्राम पथर्री के किसान श्रवण सिंह, जयराम नेताम, धनसिंग नेताम ने बताया कि सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं होने से बमुश्किल खरीफ फसलों की खेती कर पाते थे। आज स्थिति यह है कि खरीफ साथ-साथ अब वह रबी फसलों की भी खेती करने लगे हैं। इससे उनकी आमदनी बढ़ी है। जीवन स्तर में बदलाव आया है। इसी तरह विकासखण्ड देवभोग के ग्राम कुम्हडईकला के किसान शेषमल गिरिराज एवं तुलसीदास पात्रा पहले सिंचाई साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण कृषि जमीन होते हुये भी फसल नहीं ले पा रहे थे, पर सौर सुजला ने उनकी सिंचाई समस्या खत्म कर दी है। अब वह अपनी जमीन पर सब्जी की भरपूर खेती करने लगे हैं। सोलर पंप लगाने से उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है।

नीति आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ में "मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान" के सफल क्रियान्वयन की सराहना

मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का असरः कुपोषित बच्चों की संख्या में 32 प्रतिशत की आई कमी

ढाई साल में करीब डेढ़ लाख बच्चे कुपोषण मुक्त

का नीति आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा संचालित महत्वकांक्षी "मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान" की विशेष रूप से सराहना की गई है। आयोग द्वारा ट्विट कर छत्तीसगढ़ में इसके सफल क्रियान्वयन और उपलब्धि को उल्लेखित कर बधाई दी गई है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की कुपोषण मुक्ति की पहल पर छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 से शुरू हुए प्रदेशव्यापी मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का अच्छा प्रतिसाद मिलने लगा है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के साथ विभिन्न योजनाओं के एकीकृत प्लान और समन्वित प्रयास से बच्चों में कुपोषण दूर करने में बड़ी सफलता मिली है। प्रदेश में जनवरी 2019 की स्थिति में चिन्हांकित कुपोषित बच्चों की संख्या 4 लाख 33 हजार 541 थी, इनमें

से मई 2021 की स्थिति में लगभग एक तिहाई 32 प्रतिशत अर्थात एक लाख 40 हजार 556 बच्चे कुपोषण से मुक्त हो गए है। जो कुपोषण के खिलाफ शुरू की गई जंग में एक बड़ी उपलब्धि है। बहुत ही कम समय में ही प्रदेश में कुपोषण की दर में उल्लेखनीय कमी आई है, इसका श्रेय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कुशल नेतृत्व और उनकी दूरदर्शी सोच को जाता है।

छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री बघेल ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के आंकड़ों में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और एनीमिया की दर को देखते हुए प्रदेश को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त करने अभियान की शुरूआत की। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण-4 के अनुसार प्रदेश के 5 वर्ष से कम उम्र के 37. 7 प्रतिशत बच्चे कुपोषण और 15 से 49 वर्ष की 47 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थे। इन आंकड़ों को देखे तो कुपोषित बच्चों में से अधिकांश आदिवासी और दूरस्थ वनांचल इलाकों के बच्चे थे। राज्य सरकार ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और 'कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़' की संकल्पना के साथ महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरूआत की। अभियान को सफल बनाने के लिए इसमें जन-समुदाय का भी सहयोग लिया गया।

अब ममता की दिल्ली पर नजर

'भवानीपुर में ममता बनर्जी की जीत कोई मुद्दा नहीं थी। हमारा लक्ष्य था जीत के अंतर को बढ़ाना और भवानीपुर से पूरे देश को संदेश देना। टीएमसी को इसमें भारी कामयाबी मिली है। अब हमारा लक्ष्य वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को दिल्ली की कुर्सी से हटाना है। वही असली जीत होगी।'

पहले दिन से ही भवानीपुर में ममता के चुनाव अभियान का जिम्मा संभालने वाले तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने उपचुनाव के नतीजे के एलान के बाद ये बात कही। उधर, रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल करने के बाद ममता ने कहा, 'भवानीपुर के लोगों ने नंदीग्राम की साज़िश का जवाब दे दिया है।' टीएमसी नेता की इस टिप्पणी ने पार्टी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एजेंडा साफ कर दिया है। भवानीपुर सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज कर ममता ने अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। महज 57 फीसदी मतदान के बावजूद उन्होंने इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिबरेवाल को करीब 59 हजार वोटों के अंतर से पराजित कर दिया है।

बीजेपी दफ़्तर का हाल

भवानीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के लिए नाक का सवाल बन गया था। दरअसल, भवानीपुर में सवाल कभी यह नहीं रहा कि ममता जीतेंगी या नहीं। यहां सबसे बड़ा सवाल था कि वे कितने वोटों के अंतर से जीतेंगी? भवानीपुर सीट का नतीजा सामने आते ही तृणमूल कांग्रेस खेमे में जहां जश्न का माहौल है वहीं बीजेपी खेमे में सन्नाटा पसरा है। सुबह से न तो कोई नेता नजर आ रहा है और न ही कार्यकर्ता। बीजेपी के मुख्यालय और चुनाव कार्यालय में भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात हैं। लेकिन वहां सुबह से कोई नेता या कार्यकर्ता नहीं पहुंचा है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बीबीसी से कहा, 'यह नतीजा तो प्रत्याशित ही था।' ममता ने करीब 59 हजार वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। इससे पहले वर्ष 2011 में हुए उपचुनाव में यहां वे करीब 54 हजार वोटों से जीती थीं। वर्ष 2016 में उनकी जीत का अंतर करीब 25 हजार था जबकि इस साल अप्रैल में हुए चुनाव में टीएमसी उम्मीदवार शोभनदेव चटर्जी ने करीब 29 हजार वोटों से जीत हासिल की थी। इससे साफ है कि अबकी जीत का अंतर दोगुने से ज्यादा है।

बीजेपी दफ़्तर का हाल

भवानीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी)

के लिए नाक का सवाल बन गया था। दरअसल, भवानीपुर में सवाल कभी यह नहीं रहा कि ममता जीतेंगी या नहीं। यहां सबसे बड़ा सवाल था कि वे कितने वोटों के अंतर से जीतेंगी? भवानीपुर सीट का नतीजा सामने आते ही तृणमूल कांग्रेस खेमे में जहां जश्न का माहौल है वहीं बीजेपी खेमे में सन्नाटा पसरा है। सुबह से न तो कोई नेता नजर आ रहा है और न ही कार्यकर्ता। बीजेपी के मुख्यालय और चुनाव कार्यालय में भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात हैं। लेकिन वहां सुबह से कोई नेता या कार्यकर्ता नहीं पहुंचा है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बीबीसी से कहा, 'यह नतीजा तो प्रत्याशित ही था।' ममता ने करीब 59 हजार वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। इससे पहले वर्ष 2011 में हुए उपचुनाव में यहां वे करीब 54 हजार वोटों से जीती थीं। वर्ष 2016 में उनकी जीत का अंतर करीब 25 हजार था जबकि इस साल अप्रैल में हुए चुनाव में टीएमसी उम्मीदवार शोभनदेव चटर्जी ने करीब 29 हजार वोटों से जीत हासिल की थी। इससे साफ है कि अबकी जीत का अंतर दोगुने से ज्यादा है।

उन्होंने कहा कि फिलहाल बाढ़ पीड़ितों के समर्थन में खड़ा होना जरूरी है। ममता ने 30 अक्तूबर को चार सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का भी एलान किया। वैसे, चुनाव आयोग ने पहले ही विजय रैलियों पर पाबंदी लगा दी है। चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को रविवार सुबह भेजे गए एक पत्र में ममता बनर्जी सरकार से कहा कि वह ऐसे तमाम जरूरी कदम उठाए जिनसे नतीजे आने के बाद किसी भी तरह की कोई हिंसा न हो। ध्यान रहे कि पिछली बार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही राज्य में भारी हिंसा भड़की थी और कई जगहों पर आगजनी की खबरें भी सामने आई थीं। बीजेपी ने उस दौरान पश्चिम बंगाल की हिंसा के लिए टीएमसी समर्थकों पर आरोप लगाया था।

अब 2024 पर है नजर

टीएमसी के वरिष्ठ नेता फिरहाद हकीम कहते हैं, 'बीजेपी कहीं मुकाबले में ही नहीं थी। उससे पहले ही लड़ाई से हट जाना चाहिए था। इसके बाद अब दिल्ली जाना होगा। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली की कुर्सी से मोदी सरकार को हटाना ही असली जीत होगी। पूरे देश को लोग ममता को ही मोदी-विरोधी चेहरे के तौर पर देखना चाहते हैं।' इस बीच, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि चुनाव के नतीजे इलाके के लोगों में ममता बनर्जी के प्रति उत्साह का सबूत नहीं हैं। उन्होंने कहा, 'ममता का इलाका होने के बावजूद राज्य में सबसे कम वोट यहीं पड़े थे। इससे साफ है कि ममता के प्रति लोगों में पहले की तरह भारी उत्साह नहीं है।' कांग्रेस नेता का कहना था कि ममता की जीत की भविष्यवाणी करना कोई मुश्किल नहीं था। यह तो सबको पहले से मालूम था। लेकिन मतदान के प्रतिशत से लोगों के उत्साह का पता नहीं चलता। भवानीपुर के अलावा मुर्शिदाबाद जिले के दो सीटों–जंगीपुर और शमशेरगंज में भी 30 सितंबर को उपचुनाव हुआ था। जंगीपुर में वाम मोर्चा उम्मीदवार के निधन की वजह से बीते अप्रैल में मतदान स्थगित हो गया था। शमशेरगंज में भी कांग्रेस उम्मीदवार की मतदान से पहले ही मौत हो गई थी। इन दोनों सीटों पर भी टीएमसी अपने प्रतिद्वंद्वियों से काफी आगे है और उसकी जीत लगभग तय है। जंगीपुर लंबे समय तक कांग्रेस का गढ़ रहा था। बीच में वाममोर्चा के घटक आरएसपी का भी कुछ समय तक इस सीट पर कब्जा रहा। लेकिन वर्ष 2016 में तृणमूल कांग्रेस के जाकिर हुसैन की जीत के साथ यहां पार्टी का खाता खुला था। जाकिर ममता सरकार में मंत्री भी रहे। शमशेरगंज सीट वर्ष 2011 में वाममोर्चा के कब्जे में आई थी। लेकिन 2016 के विधानसभा में यहां भी तृणमूल उम्मीदवार की जीत हुई थी। राजनीतिक राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि भवानीपुर सीट से ममता की जीत पर कोई संदेह नहीं था। बीजेपी खुद को मुकाबले में जरूर बता रही थी। लेकिन नतीजों से साफ हो गया है कि कौन कितने पानी में है। राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर समीरन पाल कहते हैं, 'ममता इस सीट पर भारी अंतर से जीत कर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक कड़ा संदेश देना चाहती थीं। उन्होंने कहा भी है कि यह खेल भवानीपुर से शुरू होकर केंद्र की जीत पर ही खत्म होगा। यही वजह है कि मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी ने इस उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक दी थी।'

एयर पॉल्यूशन से गर्भ में पल रहे बच्चे को खतरा

60 लाख बच्चों की प्री-मैच्योर डिलीवरी

एयर पॉल्यूशन का असर गर्भवती महिलाओं और उनके होने वाले बच्चों पर काफी खतरनाक ढंग से दिख रहा है। रिसर्च की मानें तो साल 2019 में समय से पहले जन्मे 60 लाख बच्चे दरअसल एयर पॉल्यूशन की देन थी। 204 देशों के आंकड़ों को शामिल किया गया था।

गर्भ पर एयर पॉल्यूशन से क्या है खतरा

ऑटिज्म : हार्वर्ड की स्टडी के अनुसार गर्भावस्था के तीसरे महीने ज्यादा पॉल्यूटेड एयर में सांस लेने से बच्चे में ऑटिज्म का दोगुना खतरा रहता है।
अस्थमा : प्रेगनेंसी में अस्थमा की वजह हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है और लिवर और किडनी में कई तरह की दिक्कत हो सकती है। ये प्रीमैच्योर बर्थ और लो बर्थ वेट का भी कारण बन सकता है।
मिसकैरेज का खतरा : रिसर्च की मानें तो लंबे समय तक एयर पॉल्यूशन में रहने का संबंध मिसकैरेज से होता है। एयर पॉल्यूशन से महिलाओं और पुरुषों की फर्टिलिटी भी कम होती है।

प्रीमैच्योर बच्चों की देखभाल कैसे करें:

NICU: नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट (NICU) उन बच्चे की विशेष देखभाल करता है , जिन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं। वे बच्चे को सांस लेने, खिलाने और उन्हें गर्म रखने में मदद कर सकते हैं।
कंगारू मदर केयरः यह एक ऐसी तकनीक है, जिसमें लंबे समय तक त्वचा से त्वचा का संपर्क होता है, जिसमें मां शिशु को सीने से लगाकर रखती है।इस तकनीक से मां और बच्चे के बीच एक मजबूत रिश्ता बन जाता है।
इंफेक्शन से बचाएंः प्रीमैच्योर बच्चों में इंफेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा होता है इसलिए उनके आसपास का वातावरण पूरी तरह से साफ रखें। बच्चे को इंफेक्शन और एलर्जी से बचाकर रखना महत्वपूर्ण है। बच्चे को सांस लेने में तकलीफ न हो, इसके लिए वेंटीलेशन बैग या मास्क का उपयोग किया जा सकता है।
ब्रेस्टफीडिंगः मां का दूध बच्चे के लिए सबसे अच्छा माना जाता है । इसलिए बच्चे के जन्म के साथ ब्रेस्टफीडिंग कराएं अगर मां के लिए ये मुमकिन नहीं तो बोतल से दूध देते हुए बोतल को संक्रमणरहित करने का पूरा खयाल रखें।
बच्चे की नींद का ध्यान रखेंः बच्चे के लिए नींद पूरी होने का पूरा ख्याल रखें,उसके आसपास शोर-शराबा ना हो। बच्चों के कमरे की लाइट हल्की रखें ताकि उसे अच्छी नींद आए।
कमरे का तापमान सही रखेंः कमरे का तापमान सही रखें। न वो ज्यादा गर्म हो

प्रदूषण के मामले में भारत में क्या हैं हालात?

दुनियाभर के पॉल्यूटेड शहरों की रैंकिंग में भारतीय शहरों की संख्या बढ़ी है। जहरीली हो रही हवा से हर साल लाखों लोगों की मौत हो रही है। दुनिया के दूसरे शहरों के मुकाबले उत्तर भारत में पॉल्यूशन का स्तर 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। वहीं एक डेटा बताता है कि भारत समेत पाकिस्तान और बांग्लादेश में एयर पॉल्यूशन के कारण हर साल 3.49 लाख महिलाएं गर्भपात का शिकार हो रही हैं।

ये हवा बढ़ा रही खतरा

हवा में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार पीएम 2.5 प्रेगनेंसी के दौरान बुरा असर डालते हैं। पीएम 2.5 बेहद बारीक कण होते हैं जो बाल से भी पतले होते हैं, जिसे इंसान नंगी आंखों से देख नहीं सकता। एयर पॉल्यूशन के लिए सिर्फ ट्रैफिक और पावर प्लांट्स से निकलने वाला धुआं और गैस ही नहीं, इनडोर पॉल्यूशन भी जिम्मेदार है।

जन्म के कुछ महीनों के भीतर मौत

विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि दुनियाभर में हर साल समय से पहले जन्म लेने वाले 10 लाख बच्चों की मौत हो जाती है। ऐसे बच्चे कमजोर होते हैं और इनका वजन भी कम होता है, इसलिए इनमें कई बीमारियों का खतरा हमेशा बना रहता है। अगली पीढ़ी को सुरक्षित रखना है तो वायु प्रदूषण को कंट्रोल करना होगा।

पॉल्यूशन से बचने के तरीके

- बाहर निकलते हुए एयर पॉल्यूशन से बचने के लिए बढ़िया क्वालिटी का पॉलयूशन मास्क पहने।
- घर के अंदर की हवा को शुद्ध करने के लिए एयर प्यूरीफाइंग गुण वाले पौधे लगाएं, जैसे रबर प्लांट, तुलसी।
- प्रेग्नेंसी के दौरान योग करने को रुटीन में शामिल करें।
- प्रेग्नेंसी के दौरान चाय और कॉफी न पियें।
- खाने के साथ कोई भी खट्टी चीजें खाएं। जैसे, टमाटर , आंवला, धनिया और पुदीने का 0 रोजाना उपयोग करना प्रेग्नेंट वुमन के लिए फायदेमंद होगा।

कोरोना का 'दीघार्यु' पर असर

लोगों की औसत आयु घटी

कोरोना वायरस महामारी ने 'दीघार्यु' के आशीर्वाद को बेकार कर दिया है। कोरोना की वजह से दुनियाभर में औसत आयु कम हो गई है। यह दावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने साल 2020 की मौतों के आंकड़ों के आधार पर किया है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी में पब्लिश हुई स्टडी कहती है कि यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किसी एक साल में इंसानों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा में आई सबसे बड़ी गिरावट है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनियाभर में 29 सितंबर तक 47 लाख लोगों की मौत कोविड-19 की वजह से हुई है। इसमें भी अमेरिका में सबसे अधिक 7.11 लाख मौतें हुई हैं। उसके बाद ब्राजील (5.95 लाख) और भारत (4.47 लाख) का नंबर आता है।

इस स्टडी का मकसद क्या है?

लाइफ एक्सपेक्टेंसी को पीरियड लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कहा जाता है। इसके जरिए जन्म के समय किसी व्यक्ति की औसत आयु का अनुमान लगाया जाता है। जीवन प्रत्याशा जीवन का वास्तविक अनुमान नहीं होती बल्कि उस समय की मृत्यु दर को आधार बनाकर भविष्य में किसी व्यक्ति का जीवन कितना लंबा रहेगा, इसका आकलन किया जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का मकसद यह पता करना था कि अलग-अलग देशों में कोविड-19 ने जीवन काल यानी लंबी उम्र

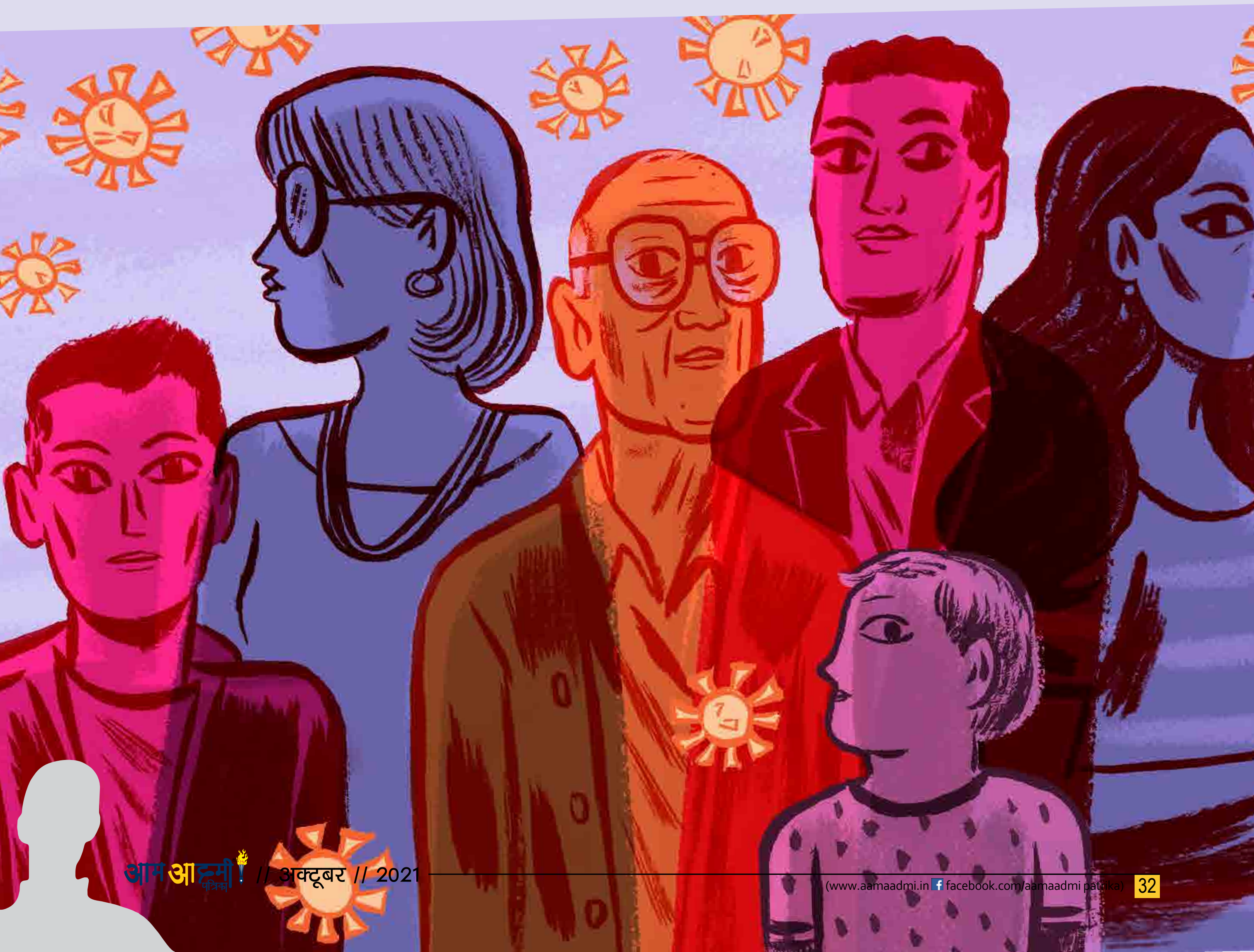

पर क्या असर डाला है। महामारी की वजह से किसी देश की आबादी की मृत्यु दर पर पड़ने वाले असर को जानने के लिए जीवन प्रत्याशा का इस्तेमाल एक प्रमुख इंडिकेटर के तौर पर होता है।

क्या कहती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी?

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने उन 29 देशों का एनालिसिस किया, जिन्होंने 2020 में हुई मौतों के आंकड़े पब्लिश किए हैं। इनमें यूरोप के ज्यादातर देशों के साथ-साथ अमेरिका और चिली भी शामिल हैं। इस स्टडी में इन देशों में अलग-अलग एज ग्रुप्स में जीवन प्रत्याशा की दर को कैल्कुलेट किया गया है। स्टडी में 2015-2020 के बीच मृत्यु दर के ट्रेंड के आधार पर 29 देशों में लिंग और उम्र के आधार पर जीवन प्रत्याशा का अनुमान लगाया गया है। जन्म के समय और 60 वर्ष की उम्र पर यह देखा गया कि व्यक्ति का औसत जीवन कितना लंबा रह सकता है। 2020 के आंकड़ों की तुलना 2015 और 2019 के बीच के ट्रेंड्स से की गई। इससे यह पता चला कि कोविड-19 की वजह से किस देश में नागरिकों की औसत उम्र घटी है या बढ़ी है।

लैंगिक आधार पर जीवन प्रत्याशा के आंकड़े क्या कहते हैं?

सभी 29 देशों में महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की जीवन प्रत्याशा दर काफी हद तक प्रभावित हुई है। अमेरिकी पुरुषों में सबसे अधिक गिरावट दर्ज हुई है, जिनकी जीवन प्रत्याशा 2019 के स्तर के मुकाबले 2020 में 2.2 साल कम हो गई है। इसके बाद लिथुआनिया का नंबर है, जहां पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 1.7 साल कम हुई है। रिसर्च के सह-प्रमुख लेखक डॉ. रिद्धी कश्यप का कहना है कि अमेरिका में जीवन प्रत्याशा की दर सबसे अधिक घटी है, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि वहां 2020 में वर्किंग एज में मौतें अधिक हुई हैं, इससे अंडर-60 ग्रुप में जीवन प्रत्याशा घटी है। वहीं, यूरोप के ज्यादातर देशों में 60+ एज ग्रुप में मौतें ज्यादा हुईं, जिससे जीवन प्रत्याशा घटी, पर सीमित रही। डॉ. कश्यप के मुताबिक कई देशों में कोविड-19 से हुई मौतों को गिनने में कई मुद्दे सामने आए हैं। कई देशों में टेस्टिंग नहीं हुई। कोविड-19 मौतों और अन्य को बांटने में भी कमियां थीं। हमारे रिजल्ट बताते हैं कि कोविड-19 ने कई देशों को बड़े झटके दिए हैं।

स्टडी के नतीजे क्या कहते हैं?

रिसर्चर्स की टीम ने पाया कि 29 में से 27 देशों में 2020 में जीवन प्रत्याशा की दर घट गई। 2015 की तुलना में 2020 में 15 देशों में महिलाओं और 10 देशों में पुरुषों के जन्म के समय की जीवन प्रत्याशा घट गई है। रिसर्चर्स ने 2015 से तुलना की क्योंकि उस समय फ्लू सीजन में भी हजारों लोगों की जान गई थी। स्टडी के सह-प्रमुख लेखक डॉ. जोस मैनुअल अबुर्तो ने कहा कि स्पेन, इंग्लैंड और वेल्स, इटली, बेल्जियम समेत अन्य पश्चिमी यूरोपीय देशों में जीवन प्रत्याशा में किसी एक साल में इस तरह की गिरावट सिर्फ दूसरे विश्वयुद्ध के समय हुई थी। वह कहते हैं कि 22 देशों में आधे साल में जीवन प्रत्याशा में कमी देखी गई है। 8 देशों में महिलाओं और 11 देशों में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा में गिरावट आई है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इन देशों में एक साल जीवन प्रत्याशा बढ़ाने में 5.6 साल लग गए थे और कोविड-19 ने उन्हें करीब-करीब 10-15 साल पीछे धकेल दिया है।

क्या भारत में जीवन प्रत्याशा पर इसका असर हुआ है?

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च में भारत को शामिल नहीं किया गया था। इसकी वजह यह है कि भारत ने अब तक 2020 के आंकड़े पब्लिश नहीं किए हैं। इसके बाद भी हमारे यहां कोविड-19 मौतों को लेकर अलग-अलग आकलन है। सरकारी आंकड़े भले ही 4-4.5 लाख के आसपास हो, अंडर-रिपोर्टिंग एवं अन्य मुद्दों की वजह से ये संख्या अधिक भी हो सकती है। वर्ल्ड हेल्थ स्टेटिस्टिक्स की जुलाई 2021 में आई रिपोर्ट कहती है कि दुनियाभर में जीवन प्रत्याशा दर बढ़ी है। पूरी दुनिया की बात करें तो जन्म के समय औसत उम्र 73.3 वर्ष हो गई है, पर 2019 के आंकड़ों के अनुसार हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 63.7 वर्ष है। हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी वह उम्र जब तक व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ जीवन जीता है। भारत की बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70.8 वर्ष है, जबकि हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 60.3 वर्ष है। यानी दोनों ही मामलों में ग्लोबल एवरेज से हम काफी पीछे हैं। इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में भारतीय महिलाएं पुरुषों से 2.7 वर्ष आगे हैं। इस रिपोर्ट में 2020 के आंकड़े शामिल नहीं थे, इस वजह से यह नहीं कहा जा सकता कि कोविड-19 का लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर क्या असर पड़ा है।

दुनिया में हवाला का बड़ा कारोबार

> रुपये को दुनिया के एक हिस्से से दूसरी जगह ट्रांसफर करना और वो भी बगैर उसे हिलाए हुए। इसके लिए न तो बैंकों की जरूरत है न ही करेंसी एक्सचेंज की, न तो कोई फॉर्म भरना है और ना ही फीस देनी है। होगा तो एक वो जो रुपये भेजेगा दूसरा वो जिसके पास रुपये आएंगे और बीच में कम से कम दो मध्यस्थ।

ये हवाला कारोबार है जो पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम आने से बहुत पहले भी था। और अपने इस्तेमाल करने में आसानी और संलिप्त लोगों को मिलने वाले कई फायदे की वजह से सदियों से चला आ रहा है। इसके जरिए दुनिया भर में लाखों डॉलर इधर से उधर किए जा सकते हैं, यह जाने बगैर कि राशि कितनी है और इसे नियंत्रित कौन कर रहा है। रुपये को दुनिया की एक जगह से दूसरे पर गैरकानूनी रूप से हस्तांतरण का नाम ही हवाला है और इसमें सबसे अहम भूमिका एजेंट या बिचौलिए या जिसे मध्यस्थ कह सकते हैं, उसकी होती है। क्योंकि ये बिचौलिए शायद ही कभी किसी लेन देन का रिकॉर्ड छोड़ते हैं। तो ये वो हैं जो हवाला के जरिए रुपया कहां से निकल कर कहां पहहुंच रहा है इसे पता लगाने में सबसे बड़ी बाधा होते हैं। और खुद को संभावित मनी लॉन्डरिंग (धन शोधन), नशीले पदर्थों की तस्करी (ड्रग ट्रैफिकिंग) और चरमपंथी संगठनों के वित्तपोषण के लिए भी भाड़े पर दे सकते हैं। मैड्रिड के पॉन्टिफिसिया कोमिला यूनिवर्सिटी में इंटरनैशनल स्टडीज के प्रोफेसर अल्बर्टो प्रीगो मोरेनो ने बीबीसी मुंडो को बताते हैं, 'हालांकि हवाला खुद इन गतिविधियों ने नहीं जुड़ा है, यह गलत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक साधन हो सकता है।' वास्तव में यह फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया में फैला हुआ है।

इसे ऐसे समझें

इसे एक पारंपरिक और अनौपचारिक तरीके के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी भी अन्य बैंकिंग सिस्टम के समानान्तर चलता है और अपने बिचौलियों की अहमियत और भरोसे पर आधारित है। उदाहरण के लिए, न्यूयॉर्क से कोई व्यक्ति बिना कोई बैंक खाता खोले ही इस्लामाबाद में पैसे भेज सकता है। इसके लिए उसे स्थानीय बिचौलिए से संपर्क करके उसे डॉलर में राशि और वो पासवर्ड देनी होती है जिस पर पैसे भेजने वाला और उसे प्राप्त करने वाला दोनों सहमत होते हैं। यानी यह पासवर्ड अब उन दोनों के अलावा बिचौलिए को भी पता होती है। अब स्थानीय बिचौलिया पाकिस्तान की राजधानी में वहां के बिचौलिए से सम्पर्क करता है और उसे वो राशि और पासवर्ड बताता है। ये दूसरा बिचौलिया उतनी ही राशि का पाकिस्तानी रुपया उस व्यक्ति को देता है जिसे पैसे डिलीवर किए जाने थे। वो यह सुनिश्चित करता है कि पैसा सही व्यक्ति तक पहहुंचे, वो उससे पासवर्ड पूछता है। यह पूरी प्रक्रिया महज कुछ घंटों में पूरी हो जाती है और बिचौलिए एक छोटी राशि बतौर कमीशन अपने पास रखता है।

हवाला आया कहां से?

हवाला की शुरूआत कब हुई यह स्पष्ट नहीं है लेकिन कुछ लोग इसे 8वीं शताब्दी से सिल्क रूट के तहत भारत से जोड़ते हैं। सिल्क रूट को प्राचीन चीनी सभ्यता के व्यापारिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। दो सौ साल ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी के बीच हन राजवंश के शासन काल में रेशम का व्यापार बढ़ा। पहले रेशम के कारवां चीनी साम्राज्य के उत्तरी छोर से पश्चिम की ओर जाते थे। लेकिन फिर मध्य एशिया के कबीलों से संपर्क हुआ और धीरे-धीरे यह मार्ग चीन, मध्य एशिया, उत्तर भारत, आज के ईरान, इराक और सीरिया से होता हुआ रोम तक पहहुंच गया। गौरतलब है कि इस मार्ग पर केवल रेशम का व्यापार नहीं होता था बल्कि इससे जुड़े सभी लोग अपने-अपने उत्पादों का व्यापार करते थे। लेकिन सिल्क रूट पर अक्सर चोरी और लूट होती थी इसलिए भारतीय, अरब और मुस्लिम व्यापारियों ने अपने मुनाफे की रक्षा के लिए अलग अलग तरीके अपनाए।

हवाला का अर्थ है 'के एवज में' या 'के बदले में'।

व्यापारी एक पासवर्ड का इस्तेमाल करते थे जो कि कोई वस्तु, शब्द या कोई इशारा होता था और ठीक उसी तरह की पूरक वस्तु, शब्द या पासवर्ड उसे प्राप्त करने वाले को बताना होता था। इस तरह, वो सुनिश्चित किया करते थे कि पैसे या सामानों की लेन देन सही हाथों तक पहहुंच जाए। यह व्यवस्था कितनी पुरानी थी

इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत में पहला बैंक 'बैंक ऑफ हिंदुस्तान' था जिसकी स्थापना 18वीं शताब्दी में कोलकाता में हुई थी। आज तकनीक के मामले में दुनिया जिस तेजी से आगे बढ़ रही है उसी आसानी से हवाला के काम को करना भी आसान हुआ है। आज इंस्टैंट मैसेजिंग एप्लिकेशन के जरिए पासवर्ड की जगह कोड भेजे जाते हैं। लिहाजा बिचौलिए भी अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के समानांतर इसे भी बेहद आसानी से अंजाम दे सकते हैं।

लेकिन ये लेनदेन गुप्त तरीके से क्यों किए जाते हैं

प्रोफेसर अल्बर्टो प्रीगो मोरेनो कहते हैं कि, 'ऐसा इसलिए होता है, कई बार ये घोषित पैसे नहीं होते हैं यानी पूरी तरह से वैध नहीं होते। कई बार (यूजर) टैक्स देने से बचता है। वहीं जब वो बतौर रिमिटेंस यह पैसे दूसरे देश में भेजता है तो वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि बतौर कमीशन बिचौलिया कम से कम पैसे रखे।' ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अमेरिका से दूसरे देश में स्थित अपने परिवार को पारंपरिक तरीके से पैसे भेजना चाहता है तो इसके लिए उसे कई मांगों को पूरा करना पड़ता है। अगर आप बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास एक निश्चित राशि होनी चाहिए। आप खाता खोल सकें इसके लिए आपके पास आपकी पहचान, वहां आपकी कानूनी स्थिति आदि जैसे कुछ दस्तावेज चाहिए होते हैं। अन्य मनी ट्रांसफर सेवाएं अंतरराष्ट्रीय लेन देन के लिए आपसे 20 फीसद तक कमीशन ले सकती हैं। चाहे मामला कोई भी हो, यूजर को कई नियंत्रणों से गुजरना पड़ता है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों से बचा जा सके।

लेकिन हवाला में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है।

प्रीगो मोरेनो कहते हैं, 'यह इतना अधिक प्रभावी है क्योंकि इसमें प्राप्तकर्ता तक पैसे अपेक्षाकृत जल्दी पहुंच जाते हैं और बतौर कमीशन भी कम देना पड़ता है।' बिचौलिए के लिए उसका नेटवर्क अच्छा होना बेहद जरूरी है। जितना अधिक आपके पास कॉन्टैक्ट होगा उतना ही अच्छा आपका बिजनेस चलेगा। लिहाजा आप बहुत कम चार्ज करें और ज्यादा से ज्यादा फायदा दें।' बिचौलिए को भरोसेमंद होने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। पहले सूदखोरी और ब्याज का प्रचलन कम था और बिचौलिए के लिए बहुत सारा पैसा बनाना मुश्किल था। यही कारण था कि पश्चिमी देशों की तुलना में यह व्यवस्था मध्यपूर्व और एशिया में ज्यादा फैला जहां बैंकिंग लेनदेन पर सख्त निगरानी और नियंत्रण है।' मोरेनो कहते हैं, 'कुछ जगहों पर इन बिचौलियों पर लोग बैंक से ज्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि बिचौलियों का यह पारिवारिक और पुश्तैनी धंधा होता है जिसे वो बैंकों की तुलना में अधिक विश्वसनीय मानते हैं।' जर्मनी के फ्रैंकफर्ट स्थित मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट में दक्षिण एशिया के कानूनी इतिहास विभाग की संयोजक मारिना मार्टिन कहती हैं, 'पहले के जमाने में हवाला और उसके जैसी ही हुंडी बेहद लोकप्रिय अवधारणा थे और आज की तारीख में इसकी समझ बदल गई है क्योंकि वो आधुनिक बैंकिंग से अलग काम करते हैं।'

कितना बड़ा है हवाला का व्यापार

पारंपरिक हवाला व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा ये है कि पैसों की लेनदेन कौन कर रहा है यह सरकार या अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की पकड़ से बाहर रहता है। यह तथ्य कि लेन देन के बहुत कम या बिल्कुल ही कोई रिकॉर्ड का न होना इन पैसों की हेरफेर को पकड़ने में एक बाधा है। माना जाता है कि न्यूयॉर्क में हुए 9/11 के हमले में आतंकवादियों का वित्तपोषण भी इन्हीं गैर-पारंपरिक तरीकों से किया गया था। न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में नए और सख़्त नियमों के आने से कुछ हजार डॉलर की अंतरराष्ट्रीय लेन देन और भी जटिल हो गई है। मार्टिन कहती हैं, '9/11 के हमलों के बाद अमेरिका हवाला को आतंकवादियों को वित्तपोषण का एक संभव जरिया मानता आया है।' वे कहती हैं, 'हवाला (और अन्य गैरपारंपरिक तरीकों) को कुछ वर्षों से मनी लॉन्डरिंग और राजनीतिक भ्रष्टाचार से लेकर मानव अंगों की तस्करी जैसी कई आपराधिक गतिविधियों से जोड़ा जाता रहा है।' 2018 में संगठित अपराध और करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की एक जांच में कहा गया था कि दुबई में हवाला जैसे गैरपारंपरिक व्यवस्था का इस्तेमाल कर बड़ी संख्या में लाखों विदेशी कामगार भारत, फिलिपींस जैसे देशों में अपने परिवार को पैसे भेजते रहे हैं। इसमें बताया गया था कि ये रकम 240 करोड़ रुपये से भी अधिक है। फरवरी 2016 में अमेरिकी ड्रग इन्फोर्समेंट ऑफि स (डीईए) ने कोलंबिया और हिजबुल्लाह संगठन के बीच यूरोप के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और नशीले पदार्थों की तस्करी का संबंध को उजागर करते हुए बताया था कि लाखों यूरो और ड्रग्स की लेनदेन की गई है। डीईए के दस्तावेजों के मुताबिक लेबनान के रास्ते लाखों के ड्रग्स मध्यपूर्व पहुंचाए गए और इसके बदले में हवाला के जरिए यूरो कोलंबिया भेजे गए थे। पूर्वी अफ्रीका, खास कर सोमालिया में हथियारों के तस्कर हवाला का इस्तेमाल कर लाखों डॉलर इधर से उधर करते हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, विकासशील देशों में रेमिटेंस के जरिए अपने परिवारों की मदद के लिए पैसे भेजने वाले प्रवासी कामगारों की संख्या में इजाफा हुआ है। कोविड-19 महामारी के प्रभाव के बावजूद आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक निम्न और मध्य आय वाले देशों में भेजी जाने वाली रेमिटेंस 2020 में लगभग 400 खरब रुपये थी। यह राशि 2019 के मुकाबले महज 1. 6 फीसद कम है। 2019 में यह आंकड़ा 406. 31 खरब रुपये था। हालांकि वर्ल्ड बैंक यह भी स्पष्ट करता है कि 'रेमिटेंस का वास्तविक आकार, जो पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों जरिए से पहुंचाया जाता है, आधिकारिक आंकड़े से कहीं बड़ा है।' अर्थव्यवस्था में संभावित वैश्विक सुधार के साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि पारंपरिक और गैर पारंपरिक माध्यमों जैसे कि हवाला से निम्न और मध्य आय वाले देशों को भेजे जाने वाली रेमिटेंस की राशि 2021 और 2022 में और भी बड़ी हो जाएगी।

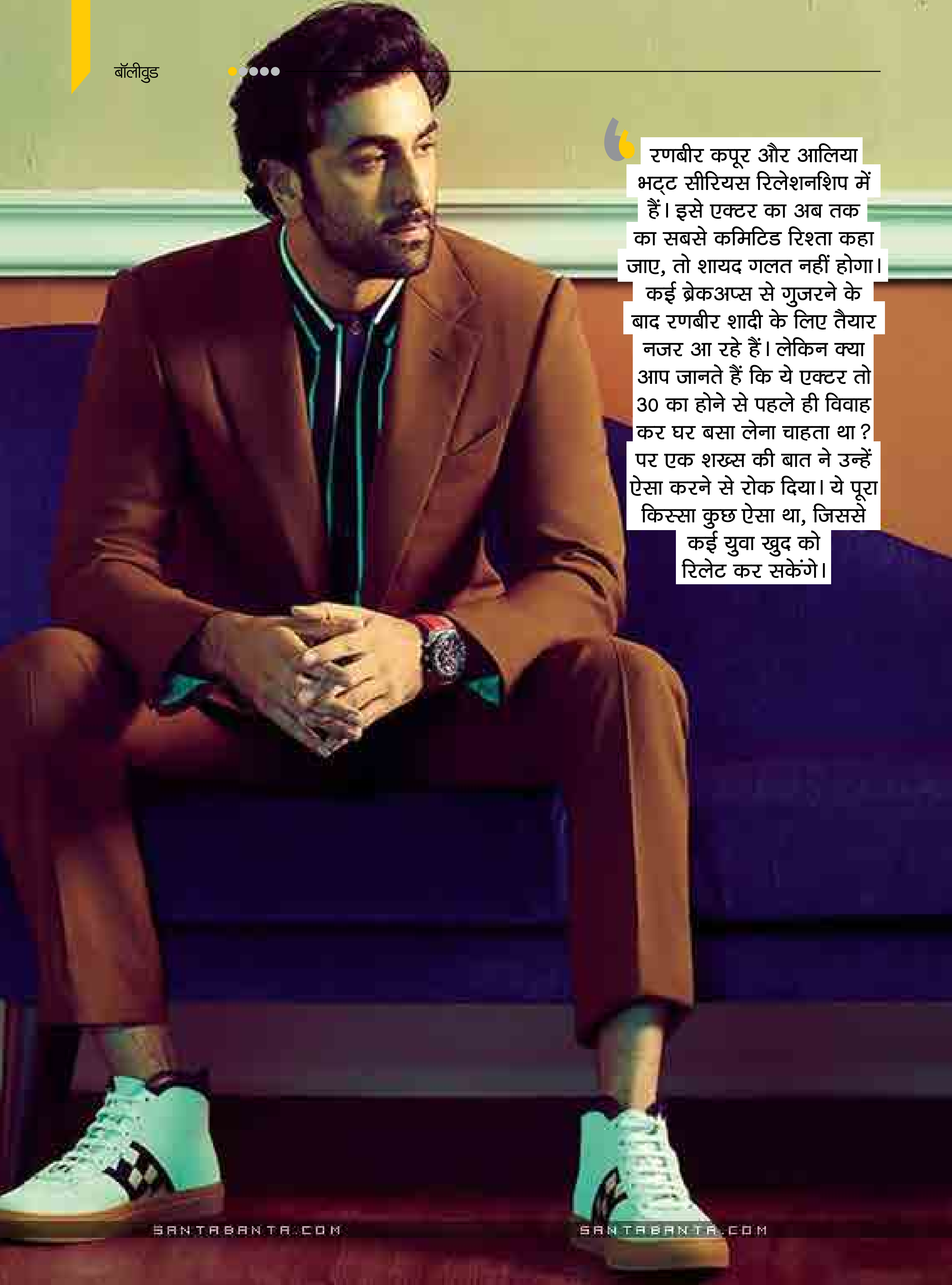

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट सीरियस रिलेशनशिप में हैं। इसे एक्टर का अब तक का सबसे कमिटिड रिश्ता कहा जाए, तो शायद गलत नहीं होगा। कई ब्रेकअप्स से गुजरने के बाद रणबीर शादी के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एक्टर तो 30 का होने से पहले ही विवाह कर घर बसा लेना चाहता था? पर एक शख्स की बात ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। ये पूरा किस्सा कुछ ऐसा था, जिससे कई युवा खुद को रिलेट कर सकेंगे।

आखिर कौन था वो जिसने रणबीर कपूर को शादी करने से रोका

रणबीर ने खुद किया था खुलासा

रणबीर कपूर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि कैसे वह 20-30 की उम्र के बीच ही शादी और बच्चे कर आम पारिवारिक जिंदगी जीना चाहते थे, लेकिन उनके दोस्त के शब्दों ने उनकी सोच को बदल दिया। एक्टर ने शेयर किया था कि वह बस यही कहते रहते थे कि 'मुझे शादी करना है, मुझे शादी करना है और मैं बच्चे चाहता हूं।' इस पर फिल्ममेकर और उनके दोस्त अयान मुखर्जी ने उन्हें सलाह दी थी कि 'तुम अभी अपने करियर की शुरूआत ही कर रहे हो। लोगों से मिलो, अपनी जिंदगी जिओ और फिर शादी के बारे में सोचना।

शादी की कोई डेडलाइन नहीं

आगे एक्टर ने अपनी राय बताते हुए कहा था कि 'हम ऐसे समय में रह रहे हैं, जब हमें शादी की उम्र को लेकर डेडलाइन नहीं दी जानी चाहिए। जब किसी को प्यार होगा, तो उसकी शादी भी हो ही जाएगी और फिर बच्चे होंगे। मुझे लगता है कि ये सब नैचरल प्रोग्रेस है' । रणबीर ने ये जाहिर किया था कि उनकी सोच में बदलाव अयान से मिलने के बाद ही आया। रणबीर कपूर की सोच को बदलने में भले ही उनके दोस्त का हाथ हो, लेकिन मौजूदा समय में कई युवा शादी को लेकर यही रुख अपनाते दिख रहे हैं। पहले जहां बालिग होते ही या फिर नौकरी लगते ही शादी कर दी जाती थी, वहीं आज के वर्किंग यंगस्टर्स करियर में सेटल हो जाने और अपनी जिंदगी को थोड़ा इंजॉय कर लेने के बाद ही परिवार के बंधन में बंधने के बारे में सोचते हैं।

लड़कियों की सोच में भी आ रहा अंतर

ये सोच सिर्फ लड़कों ही नहीं, बल्कि लड़कियों में भी देखने को मिल रही है। आजकल लड़कियां शादी से पहले करियर बनाना चाहती हैं और विवाह के बंधन में बंधने के बाद भी नौकरी जारी रखना पसंद करती हैं। काम के जरिए आर्थिक रूप से मिलने वाली मजबूती उन्हें न सिर्फ अपनी लाइफ सिक्यॉर बनाने में मदद करती है, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ी को भी बेहतर भविष्य देने में मदद करती है।

ये भी है वजह

वैसे लड़के और लड़कियों की सोच में आने वाले अंतर के पीछे की एक वजह अपना जीवनसाथी खुद चुनने की आजादी बढ़ना भी है। पहले ज्यादातर अरेंज्ड मैरिज ही हुआ करती थी, लेकिन अब माता-पिता भी अपने बच्चों की पसंद को स्वीकारने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर बढ़ती महंगाई और बदलता लाइफस्टाइल जिसके लिए ज्यादा आर्थिक मजबूती की जरूरत होती है, उसे देखते हुए ज्यादातर लोग न सिर्फ अपना मजबूत करियर चाहते हैं, बल्कि उम्मीद रखते हैं कि उनका साथी भी वर्किंग हो।

माह : अक्टूबर 2021

राशिफल

मेष

जीवन में रोमांचपूर्ण और भावनात्मक प्रगाढ़ता आएगी। परोपकारी, दान-पुण्य, सामाजिक कार्य, सहानुभूति का योग है। कुछ अलग किस्म का बौद्धिक लाभ का योग है। आपकी छवि उस छवि के काफी नजदीक है जैसी आप बनाना चाहते हैं। यह अहसास आपको आशावादिता, विश्वास और ऊर्जा से भर देगा। आप एक बार फिर भविष्य की योजनाओं के नियोजन में जुटेंगे।

वृष

दोस्तों एवं प्रियजनों के सहयोग से व्यापारिक क्षेत्र/शैक्षिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होगी। सामाजिक/राजनैतिक/प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को असमंजसपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी स्वयं की तीव्र इच्छा आपको मजबूती से आपकी उम्मीदों की राह पर ले जाएगी। विस्तार से आज यात्रा का संयोग है या नजदीकी भविष्य में आपको आकस्मिक एवं अप्रत्याशित लाभ होंगे ।

मिथुन

आपकी राशि के लोगों का रुझान और स्वभाव आमतौर पर कलात्मक होता है, जो उन्हें मीडिया एवं कला-जगत से जुड़ी गतिविधियों में कामयाब बनाता है। इन क्षेत्रों में आप सितारे की तरह जगमगाएंगे। ताजा नया क्षेत्र आपको अपने अधीन कर लेगा, यह बताने के लिए कि वास्तव में आपकी दिलचस्पी किसमें होनी चाहिए, और यह कुछ नया, चुनौतीपूर्ण करने के लिए अनुकूल समय भी होगा। शायद गुप्त सौदे इस चरण में मूर्तरूप ले लेंगे।

कर्क

निजी और पारिवारिक सम्पत्ति के मामलों को निपटाना जरूरी होगा, लापरवाही करने से बाद में कष्ट होगा। इस बार करियर के रास्ते ग्राफ की ऊंची उड़ान तथा मकान की प्रगति/नवीकरण/वृद्धि दोनों विषय महत्वपूर्ण रहेंगे। आप घर परिवार के वायदों व जिम्मेदारियों से गहरे जुड़ें होंगे, विशेषतः बड़े बूढ़ों के सम्मान के लिए। यह बात आपके दिल के बिल्कुल पास होगी।

सिंह

कार्य, व्यवसाय में अपने लक्ष्यों के लिए यर्थाथवादी बनें। शेयर और अन्य जोखिम भरे कार्य रोचक रहेंगे। मुख्य दबाव वित्तीय मामले, धन सम्बन्धी तथ्यों से लेकर उच्च अर्थ से घरेलू बजट तक बने रहेंगे। ऋण, जमानत, संयुक्त वित्त, बोनस पेंशन एवं सेवानिवृत्ति से जुड़े निवेश महत्वपूर्ण रहेंगे। लोग अलग-अलग तरीकों से आपके लिए महत्व रखेंगे तथा आप एक आकर्षण पाएंगे, जो आप चाहते हैं।

कन्या

रिश्तेदार/मित्र/ के गृह आगमन से प्रसन्नता होगी। अध्यात्म या धर्म से जुड़े विषयों पर आप विशेष रुचि लेंगे। किसी महिला से नया व्यवहार बनेगा। भविष्य के प्रति अधिक चिंतित रहेंगे। शानदार नतीजों को दिखाने वाला समय जो आपको भरपूर ऊर्जा के संग आगे जाने को प्रेरित करेगा। भौतिक और आध्यात्मिक लाभ के आसार हैं। ऋण फंड संयुक्त वित्त के मामले सुधरेंगे और वित्तीय सफलता सुनिश्चित है।

तुला

व्यक्ति विशेष के सहयोग से किसी महत्वपूर्ण योजना की शुरूआत राजकीय/शासकीय विभाग से जुड़े व्यक्तियों की स्थिति सामान्य रहेगी। खानपान में संयम बरतना बहुत जरूरी है, खासकर ठण्डी चीजें खाने से बचें। सकारात्मक सोंच होगी। खुश होने के पर्याप्त कारण उपलब्ध होंगे। आप दुख, अवसाद, निरर्थकता, एकाकीपन या क्रोध की भावना से मुक्त होंगे। बच्चों की गतिविधियों, उपलब्धियों, विकास और वृद्धि में आप गर्व महसूस करेंगे।

वृश्चिक

खान-पान में कुछ संयम संतुलन रखना भी अभीष्ट होगा, अन्यथा स्वास्थ्य की चिन्ता रहेगी। व्यवधान भी हटेंगे। कार्यसिद्धि भी होगी। मायूसियां खत्म होंगी, साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेंगे। रिश्तों से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं। पारिवारिक संवाद जीवन्त और अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। ये अलग-अलग तरह के हो सकते हैं। इसलिए एक जटिल दिन लेकिन फलदायक भी है।

धनु

आपको बहुत से कार्य कलापों, कुछ निश्चित पार्टियों, सामाजिक एवं समाज की घटनाओं पारिवारिक आयोजनों के सम्मुख होना पड़ सकता है। आपके पास इस समय कुछ आगे करने के लिए होगा। सन्तोष शान्ति व सम्मति परिवार के कल्याण के लिए एक साथ काम करने की सहमति देगी, जो कि एक खुशनुमा समय होगा। काम में भी अधिक प्रगति होगी।

मकर

आप अपने व्यक्तित्व और छवि को बेहतर बनाने की तरफ ध्यान देंगे। आपका व्यक्तित्व, यहां तक कि कपड़े, एक्सेसरीज, परिसम्पत्ति और घर के मूल्यांकन तथा उसे नए सिरे से व्यवस्थित करने का समय है। शक्ति, नैतिक समर्थन, मांगे, निर्देशन तथा प्रेरणा के लिए वापस परिवार, प्रियजन तथा जीवन साथी की ओर मुड़ेंगे। आपके जीवन में सही आचार-व्यवहार का अभाव नहीं रहेगा।

कुंभ

आप निवेश को लेकर विचारशील रहेंगे। किसी शुभ कार्य के आरम्भ का समय अभी उचित नहीं है। किसी से कर्ज का लेन-देन न करें अन्यथा भविष्य में सम्बन्धों में बिखराव होगा। घर की मरम्मत, पुनर्निर्माण, अतिरिक्त निर्माण और यहां तक कि नए घर का निर्माण भी कर सकते हैं, साथ ही इनसे सम्बद्ध आयोजनों और समारोहों पर भी जोर देंगें। अत्यधिक काम करने की प्रवृत्ति से बचें और अपनी तथा दूसरों की देखभाल करें।

मीन

अक्टूबर- महत्वपूर्ण लोगों का समर्थन और प्यार आपको मिलेगा। व्यवसाय और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर आप नजदीकियों की अहमियत महसूस करेंगे। अपने परिवार से प्यार करने वाले आपकी राशि के लोगों के लिए अपने प्रियजनों से दूर होना तकलीफदेय होता है। एक शानदार दौर जारी रहेगा। आप सामाजिकता में दिलचस्पी लेते हैं और अपने आसपास के लोगों को पसन्द भी करते हैं।

SWITCH TO ORGANIC

Because Immunity Is What You Eat

ORGALIFE®

ORGANIC STORE

All Product Range Available At Orgalife Exclusive Store

OPP. SHRI RAM MANDIR, SHOP No.15, VIP CHOWK, RAIPUR (C.G.)

For Trade Queries/Suggestions +91-9755188822 care@orgalife.in www.orgalife.in Follow us on

छत्तीसगढ़ की अद्वितीय सांस्कृतिक धरोहर

आइये चलें आराध्य सियाराम के पदचिन्हों पर

राम वन गमन पर्यटन परिपथ

2260 किमी

हर एक कदम आस्था और विश्वास का

9 पड़ाव

पौराणिक कथाओं की जीवंतता के केंद्र

छत्तीसगढ़

ईश्वर की दिव्यता का अनुभव

Chhattisgarh
full of surprises
Chhattisgarh Tourism Board

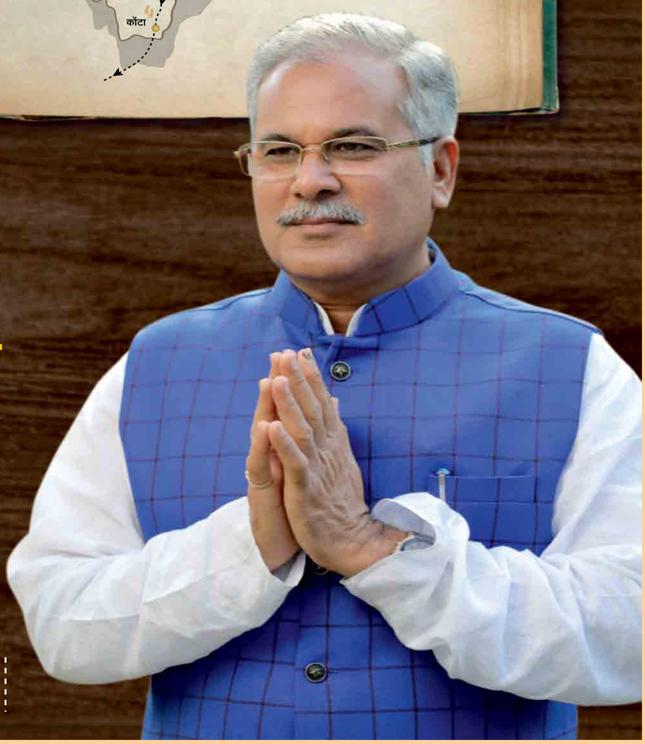

श्री भूपेश बघेल
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

R.O NO.-11628/128